(An India Newspaper)

ELARIS CONSULTING
Beyond The Visible

यूथ ऑरा
YOUTH AURA
इनोवेशन.ट्रांसफॉर्मेशन.ऑटोमेशन

(Sponsored by)
SPYeye SOLUTIONS
TRANSFORMATION AUTOMATION INNOVATION

वर्ष:01 | अंक : 19 | मंगलवार, 16-22 दिसंबर 2025 | हिन्दी साप्ताहिक | मुल्य 02 रुपये | मुख्य सम्पादकः लव जैन | RNI. NO.: HRBIL/25/A1127 | पृष्ठः 8

गोवा अग्निकांड : क्लब मालिकों को भारत लाया जा रहा

■ बैंकॉक में भारतीय एजेंसियों के हवाले किए जाएंगे

एजेंसी

गोवा। नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन आग मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थाईलैंड पुलिस ने गुरुवार (11 दिसंबर) को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। थाई पुलिस अब दोनों को बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट ले गई है। यहां दोनों को भारतीय एजेंसियां अपनी कस्टडी में लेंगी। इसके बाद उन्हें सुआन फू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। पासपोर्ट रद्द होने के कारण भारतीय दूतावास इनके लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। चूंकि, थाईलैंड से गोवा के लिए सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से पहले दिल्ली, फिर गोवा ले जाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 दिन लगेंगे। सोमवार तक दोनों भाइयों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली पहुंचते ही गोवा पुलिस दोनों को हिरासत में लेगी। इधर, लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ और गौरव, बर्च क्लब के अलावा अन्य 42 कंपनियों से भी जुड़े हैं, जिनमें कई सिर्फ कागज पर मौजूद हैं।

1984 दंगा पीड़ितों को राहत: सीएम रेखा ने सौंपे नियुक्ति पत्र

■ कहा: गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने वर्षों से न्याय और सहारे की उम्मीद लगाए इन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि सभी नियमों का सरलीकरण कर हर पीड़ित परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया। उम्र और शिक्षा से जुड़ी बंदिशें हटाई गईं ताकि वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार पिछली सरकारों में काफी समय से विभिन्न दरवाजे खटखटाते रहे और अपनी तकलीफें बताते रहे। लेकिन मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। सरकार की ओर से जारी शेष सूची के तहत भी जल्द नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।

शिवराज पाटिल के निधन पर शोक की लहर

पीएम मोदी, राजनाथ सिंह ने जताया दुख, राहुल गांधी ने बताया अपूरणीय क्षति

एजेंसी

मुम्बई। महाराष्ट्र के लातूर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पाटिल ने लातूर स्थित अपने आवास 'देवघर' में अंतिम सांस ली। पाटिल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनका घर पर इलाज जारी था। उनके निधन की खबर जैसे ही आई, कांग्रेस पार्टी सहित कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "वरिष्ठ राजनीतिक नेता शिवराज पाटिल जी के निधन से हमने एक प्रमुख जन व्यक्तित्व को खो दिया है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और दीर्घकालिक संसद सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने शिवराज पाटिल के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने पाटिल के साथ अपनी पुरानी फोटो साझा करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "शिवराज पाटिल जी के निधन से दुखी हूं। वे एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अपने

लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के तौर पर काम किया। वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ साल में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, सबसे हाल की मुलाकात तब हुई जब वे कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति।"कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पाटिल के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूरे पाटिल परिवार, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों के साथ हैं।"रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, "वह एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अलग-अलग पदों पर देश की सेवा की और भारत की तरक्की में असरदार योगदान दिया।

संसद में तमिलनाडु सरकार पर बरसे अनुराग ठाकुर

दीये जलाने और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ के आरोप

एजेंसी

नई दिल्ली। सांसद ठाकुर ने कहा, 'भारत का एक राज्य सनातन धर्म-विरोध का चेहरा बन गया है। इस राज्य के मंत्रियों ने सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए हैं।' अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो तमिलनाडु के मंदिरों में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। भाजपा सांसद ने दावा किया कि इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लोगों को कोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ठाकुर ने कहा कि मदुरै पीठ ने 'कार्तिगई दीपम' को लेकर जारी निदेर्शों को अधिकारियों की ओर से जानबूझकर पालन न करने के

आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गईं। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें महादीपम जलाने के अनुमति नहीं दी गई। मेरा सवाल है कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश क्यों नहीं माने? हिंदुओं को क्यों रोका गया?' अनुराग ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश की अवमानना की गई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मामला हो या कार्तिगई दीपम का तमिलनाडु सरकार की ओर से हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों रोका जाता है? मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर तमिलनाडु भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने कहा, 'उन पर एक विशेष समुदाय का पक्ष लेने का आरोप है, जो बिल्कुल गलत है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि एक सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि यह द्रविड़ मॉडल वाली सरकार अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही है। डीएमके की मानसिकता हिंदू-विरोधी और ब्राह्मण-विरोधी है। डीएमके और उसके सहयोगी तमिलनाडु में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।" मदुरै जिले में तिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम त्योहार पर दीपथून में महादीपम जलाए जाने की परंपरा है। दरगाह के पास होने की वजह से इसे जलाने के विरोध किया जा रहा था। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने कार्तिगई दीपम पर पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति दे दी। हालांकि, तमिलानाडु प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। इस पर हिंदू तमिलार कांची के संस्थापक की ओ से अवमानना की अर्जी दी। इस पर मदुरै पीठ ने फिर से सीआईएसएफ की सुरक्षा में दीप जलाने की मंजूरी दी। इस आदेश पर भी प्रशासन ने पहाड़ी पर दीप जलाने से लोगों को रोक दिया। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यह

राहुल गांधी ने कहा: सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए

■ लोकसभा में बोले: बच्चों का भविष्य खतरे में

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को सदन के अंदर वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदूषण की चुनौती से निपटने पर सवाल भी पूछा। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि इस कठिनाई से निपटने के लिए सरकार के पास अगले चार-पांच साल का क्या रोडमैप है? राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि हमारे अधिकांश प्रमुख शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोगों को कैंसर हो रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर मुझे यकीन है कि सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई सोच का मुद्दा नहीं है। इस सदन में हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण, और इससे हमारे लोगों को हो रहे नुकसान, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सहयोग करना चाहेंगे।"राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे कहा, "मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि हम यह न कहें कि आपने क्या नहीं किया और आप यह न कहें कि हमने क्या नहीं किया, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दें कि हम भविष्य में भारत की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने होंगे।

राहुल की सांसदों के साथ बैठक में नहीं पहुंचे थरूर, कोलकाता में दोस्त की शादी में गए

एजेंसी

नईं दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार को संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें 99 सांसद शामिल हुए थे। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, थरूर ने पहले ही पार्टी को अपनी गैरहाजिरी के बारे में जानकारी दे दी थी। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुरुवार को बताया था कि वे कोलकाता में

अपने एक पुराने दोस्त की शादी में पहुंचे हैं। यह लगातार तीसरी बार है, जब थरूर शीतकालीन सत्र से जुड़ी अहम बैठक में गैरहाजिर रहे। थरूर इससे पहले नवंबर में कांग्रेस की दो बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। पहली बैठक 30 नवंबर को हुई थी। यह रणनीतिक बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई थी। दूसरी बैठक 18 नवंबर को हुई थी। इसमें SIR प्रक्रिया को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई थी। थरूर ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली रणनीति बैठक अटेंड नहीं करने के सवाल पर 1 दिसंबर को संसद के बाहर मीडिया को जवाब दिया। उन्होंने कहा- मैंने बैठक छोड़ी नहीं थी, मैं केरल से आ रहा था और प्लेन में था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया थरूर अपनी 90 साल की मां का जन्मदिन मनाने के लिए केरल गए थे। 18 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) पर कांग्रेस सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई थी।

सुप्रीम कोर्ट बोला: करूर भगदड़ की निष्पक्ष जांच होना जरूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करूर भगदड़ मामले में पहले दिए गए अपने निर्देश को बदलने से इनकार कर दिया। अदालत ने निर्देश दोहराते हुए कहा कि CBI जांच की निगरानी करने वाले सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य तामिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने की। विजय की पार्टी TVK की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने CBI जांच के आदेश पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया। सुनवाई के दौरान

जस्टिस महेश्वरी ने कहा, हम चाहते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष हो। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर के अपने फैसले को याद किया और बताया कि यह कमेटी जांच को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए बनाई गई थी। कमेटी का नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय रस्तोगी करेंगे। उन्हें आदेश दिया गया कि वे दो वरिष्ठ क्दर अधिकारी चुनें, जो तामिलनाडु कैडर से हो सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे।

इंडिगो पर एक्शन, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड

डीजीसीए की एयरलाइन उएड से दूसरे दिन पूछताछ, बेंगलुरु एयरपोर्ट से 54 फ्लाइट कैंसिल

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में फ्लाइट कैंसिल को लेकर जारी संकट के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। DGCA ((नागरिक उड्डयन नियामक) ने शुक्रवार को एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इधर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स आज लगातार दूसरे दिन DGCA के सामने पेश होंगे। इससे पहले गुरुवार को पीटर से अधिकारियों ने करीब 2 घंटे की पूछताछ की थी। इसमें ऑपरेशंस, क्रू मैनेजमेंट, रिफंड, मुआवजे से जुड़े सवाल-जवाब किए गए। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट से शुक्रवार को इंडिगो की 54 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इनमें 31 आने वाली (अराइवल) और 23 जाने वाली (डिपार्चर) फ्लाइट शामिल हैं।

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थीं। इस बीच, देश में कम किराए वाली विमान सेवा शुरू करने वाले कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो संकट शायद इसलिए बढ़ा, क्योंकि एयरलाइन संचालकों में घमंड और ओवरकॉन्फिडेंस आ गया था।

इसलिए एयरलाइन हालात नहीं समझ पाई। 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के दूसरे फेज को लागू करने में सही प्लानिंग की कमी ही 2 दिसंबर से शुरू हुए संकट का कारण है। नए नियमों के साथ, एयरलाइन के पास अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट नहीं थे। जब बॉटम लाइन, रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ और स्टॉक मार्केट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो ऐसा होता है कि वे पायलट और दूसरे स्टाफ की बात सुनना बंद कर देते हैं। इंडिगो ने टिकट बेचने से पहले फ्लाइट्स की संख्या कम कर दी होती, तो सब कुछ ठीक होता। DGCA को पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए और इसमें कोई भाई-भतीजावाद और कोई पॉलिटिकल असर नहीं होना चाहिए। कैप्टन आर. गोपीनाथ 2003 में एयर डेक्कन लेकर आए थे। उन्होंने ही भारत में कम लागत वाली एयरलाइन (LCC) मॉडल की शुरूआत की थी। एयर डेक्कन ने एटीआर टर्बोप्रॉप विमानों के साथ ऑपरेशन शुरू किया था। हालांकि एयरलाइन के घाटे में जाने के बाद निवेशकों के दबाव में 2008 में उन्हें एयर डेक्कन को विजय माल्या को बेचना पड़ा। माल्या ने इसे किंगफिशर नाम दिया। गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को बर्बाद करने के लिए इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को दोषी ठहराया है। गुरुवार को दिल्ली और बैंगलोर एयरपोर्ट पर 200+ फ्लाइट कैंसिल हुईं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को जो आम तौर पर करीब 2,300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, अपने विंटर शेड्यूल को 10 परसेंट कम करने का भी निर्देश दिया है।

हिमंत बोले: 1 लाख रुपये भी दूं तो मुस्लिम वोट नहीं देंगे

चाहे तो किडनी दे देंगे, असम में योजना नहीं विचारधारा पर मतदान होता है

एजेंसी

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि असम में वोट योजनाओं या पैसों से नहीं, बल्कि विचारधारा और सोच से तय होते हैं। उन्होंने कहा- 'चाहे वे 10 हजार रुपए दें या 1 लाख, मुस्लिम वोटर उन्हें वोट नहीं देंगे।' सरमा दिल्ली में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह कोई योजना है, जिसमें महिलाओं को सीधे पैसे दिए जाते हैं, जैसे महिला रोजगार योजना में 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिलते हैं। सरमा ने उदाहरण देते हुए कहा- एक मुस्लिम वोटर ने मेरे काम की तारीफ की। जिन्हें हम मियां मुसलमान कहते हैं। उसने कहा कि जरूरत पड़ी तो किडनी भी दे देगा, लेकिन वोट नहीं देगा। असम में अवैध आबादी बढ़ रही है और मुस्लिम लोग बढ़ रहे हैं, जो राज्य के लिए समस्या है। 2021 में मुस्लिम आबादी 38% थी और 2027 में यह 40% तक पहुंच सकती है। 1961 से मुस्लिम आबादी हर दस साल में 4झ5% बढ़ रही है। अगर यह 50% से ज्यादा हो गई, तो बाकी लोग

मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे असम की पहचान खतरे में है। मियां मुसलमान और मुस्लिम महिलाएं हमसे अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन हमें वोट नहीं देंगे। अगर मुस्लिम वोटर सारे वोट कांग्रेस को भी दें, तो भी हमारी सरकार जीत जाएगी। सरमा ने 6 नवंबर को बिहार के पूर्णिया में कहा था कि पूर्णिया में मां पुरण देवी और काली मंदिर के साथ-साथ मां कामाख्या का भी मंदिर है। मैं जहां से आया हूं, उस असम के गुवाहाटी में भी मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है। असम, लखनऊ या कसबा हो, हर जगह हिंदू एक हैं। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। मोदी जी का नारा घर-घर पहुंच गया है, हिंदू एक है तो सेफ है।सरमा ने 5 नवंबर को बिहार के कटिहार में कहा था कि राहुल गांधी घुसपैठियों के वोट से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें भारत नहीं, बांग्लादेश जाना चाहिए। सरमा ने स्पष्ट किया कि भारत में घुसपैठियों को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा।सरमा ने 21 अगस्त को कहा था कि असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा।

दिल्ली सरकार ने 11 को 13 जिलों में पुनर्गठित करने को मंजूरी दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की रेखा सरकार ने 11 राजस्व जिलों को 13 नए जिलों में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी में शासन को सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इसमें कहा गया है कि पुनर्गठन के बाद, सभी 13 जिलों की सीमाएं पूरी तरह से एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ संरेखित हो जाएंगी, जिससे शासन में स्पष्टता आएगी और अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार होगा। गजट अधिसूचना 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी और सरकार इस महीने के अंत तक नए जिलों को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है। नई संरचना के तहत, जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 और उप-मंडलों की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी, जिससे अधिकारियों के कार्यभार को संतुलित करने और नागरिकों को अधिक तेजी से सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई वर्षों तक, राजस्व जिलों की सीमाएं दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ संरेखित नहीं थीं, जिससे बार-बार सेवा वितरण में देरी, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कठिनाइयां और विभागीय अधिकार क्षेत्र में विसंगतियां पैदा हुईं।

दिल्ली पुलिस ने 11 साल पुराना मर्डर केस सुलझाया, फरार आरोपी कासगंज से गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 11 साल पुराने एक मर्डर केस को सुलझाते हुए आरोपी लखन सिंह उर्फ अंश कुमार को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया है। लखन सिंह वर्ष 2014 में दर्ज पुलिस स्टेशन रानहोला के मर्डर केस में लंबे समय से वांछित चल रहा था और उसे 2015 में अदालत की ओर से भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व में हत्या और गंभीर मामलों को सुलझाने में जुटी टीम ने इस पुराने केस पर दोबारा काम शुरू किया। आरोपी के राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान इंस्पेक्टर पुखराज और एएसआई प्रदीप को आरोपी की मौजूदगी से जुड़ी अहम जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने बड़े स्तर पर रिकॉर्ड की जांच और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी का पता कासगंज में लगाया। इसके बाद टीम ने उत्तर प्रदेश में कासगंज में समन्वित ऑपरेशन चलाया और 11 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, ताकि वह गिरफ्तारी से बच सके, लेकिन इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह मामला 21 नवंबर 2014 को सामने आया था, जब रानहोला थाना क्षेत्र में होली कॉन्वेंट स्कूल के पास खेड़ी बाबा पुल के नाले के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। शव पर चेहरे, सिर के पीछे और शरीर के हिस्सों पर गहरे घाव पाए गए थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में मृतक की पहचान राकेश भगत के रूप में हुई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो हत्या के आरोप में लखन सिंह का नाम सामने आया, लेकिन अपराध के बाद वह फरार हो गया और पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। जांच में पता चला था कि लखन सिंह का जन्म राजस्थान के करौली में हुआ था और वह शुरुआती पढ़ाई के बाद नजफगढ़ आकर मजदूरी का काम करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह 11 वर्षों तक अलग-अलग राज्यों में छिपता रहा।

सैनिक फ़ार्म क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अधिकारियों ने बंगला गिराना शुरू किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण दिल्ली के सैनिक फ़ार्म क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने शुक्रवार को एक बंगला गिराना शुरू किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई सुबह करीब छह बजे शुरू हुई, जिसमें ढांचे को गिराने के लिए कई मशीनें तैनात की गईं। अधिकारी के अनुसार, यह भवन कथित रूप से सरकारी भूमि पर निर्मित था। उन्होंने बताया कि कार्रवाई स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। बंगले के मालिक के अनुसार, मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने बताया कि यह भूखंड 1993 में खरीदा गया था और मकान 2000 में बनाया गया था।

पूर्वी दिल्ली में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मारी गई

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने पुरानी रंजिश के कारण 50 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली मार दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार रात 10 बज कर 31 मिनट पर एक महिला की पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) कॉल आयी। महिला ने बताया कि उसके पति को गोली मार दी गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान शाहदरा के बलबीर नगर निवासी जोगेंदर राठौर उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि उसे पीठ में तीन गोलियां लगी हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'परिवार के सदस्य उसे (बिल्ला को) अस्पताल ले गए। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है।' अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात हमलावरों ने राठौर पर नजदीक से गोलियां चलाईं और फिर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि हमले का कारण पुरानी रंजिश हो सकती है। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में हत्या के प्रयास और आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के 36 सदस्यों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हालांकि कोई भी सरकारी सहायता पीड़ितों के आघात को मिटा नहीं सकती, फिर भी उनका प्रशासन उन्हें सम्मान और न्याय के साथ सहायता प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए 1984 में हिंसा से जुड़ी अपने बचपन की यादों को साझा किया

गुप्ता ने कहा, 'जब 1984 में दंगे हुए थे, तब मैं लगभग 10 साल की थी। हर कोई डरा हुआ था। लोग अपनी पहचान छिपा रहे थे। हम सबने वो भयानक दृश्य देखे हैं।' गुप्ता ने कहा कि उन दृश्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, 'कोई भी सहायता उन दिनों के दर्द को पूरी तरह से कम नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए।' मुख्यमंत्री ने दंगों से संबंधित कानूनी कार्यवाही में हुई प्रगति का श्रेय केंद्र सरकार को दिया। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एसआईटी गठित किए जाने के बाद ही मामले दोबारा खुले और दोषियों को जेल भेजा जाने लगा।'

गुप्ता ने कहा कि वह खुद को पीड़ितों को उनका हक दिलाने में मदद करने वाला एक माध्यम मात्र मानती हैं। उन्होंने कहा, 'हम सिर्फ दिल्ली के उन परिवारों के दर्द को कम करना चाहते हैं, जो लंबे समय से इस दर्द को झेल रहे हैं। हम इन परिवारों के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं।' सिरसा ने काफी समय से लंबित पुनर्वास उपायों को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि पीड़ित परिवारों ने 1984 के दंगों का दर्द दशकों तक सहा है, और यह कदम कुछ हद तक उनके घावों पर मरहम लगाने का काम करेगा।

एनडीएमसी का विशेष धूल-नियंत्रण अभियान, आवासीय क्षेत्रों में व्यापक सफ़ाई कार्य तेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली क्षेत्र में स्वच्छता स्तर को मजबूत करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने गुरुवार को अपने चुनिंदा आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशेष धूल-नियंत्रण तथा गहन सफ़ाई अभियान चलाया। यह अभियान बड़े पैमाने पर संयुक्त प्रयास के रूप में संचालित किया गया, जिसमें परिषद के स्वच्छता, बागवानी तथा नागरिक अभियंत्रण विभागों ने मिलकर भागीदारी निभाई।

अभियान के दौरान परिषद की टीमों ने मशीनों की सहायता से सड़कों और गलियों की सफाई की, साइड चैनलों से जमाव हटाया, आवश्यक मरम्मत कार्य किए तथा हरित क्षेत्रों के रखरखाव हेतु ब्लोअर मशीनों का उपयोग किया। इन सभी कदमों का मुख्य उद्देश्य धूल से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करना और क्षेत्र की समग्र पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाना रहा। विशेष सफाई अभियान में काका नगर, पश्चिम किदवई नगर, जोर बाग, सीपीएच कॉलोनी तथा शाहजहां रोड स्थित अधिकारियों के आवासों सहित कई प्रमुख आवासीय कॉलोनियों को शामिल किया गया। परिषद ने इन क्षेत्रों में सड़क, पार्कों के आसपास, सार्वजनिक परिसरों तथा संवेदनशील मार्गों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया।

इसके अतिरिक्त अनेक सर्किल क्षेत्रों में भी गहन सफाई कार्य किए गए। इसमें काका नगर (लाइब्रेरी क्षेत्र), पश्चिम किदवई नगर, सीपीएच क्वार्टर, ए एवं बी बंगला क्षेत्र, शाहजहां रोड, कॉनॉट प्लेस, केजी मार्ग से टॉल्स्टॉय मार्ग, बाराखंभा मार्ग से टॉल्स्टॉय मार्ग, मौलाना आज़ाद मार्ग (अकबर रोड से जनपथ तक), जोर बाग कॉलोनी, जी एवेन्यू रोड तथा केंद्र सरकार कर्मचारी आवासों की डिवाइडिंग रोड, बीकेएस मार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग सम्मिलित रहे।

एनडीएमसी ने कहा है कि राजधानी आने वाले नागरिकों और यहां निवासरत लोगों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। परिषद का मानना है कि सम्मिलित प्रयासों से न केवल क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि वायु की गुणवत्ता में सुधार भी प्रभावी रूप से सामने आएगा।

बदरपुर में खोली जाए एम्स की नई शाखा : बिधूड़ी

-एनटीपीसी पावर हाउस बंद होने से खाली पड़ी है जमीन

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, 12 दिसंबर (वेब वार्ता)। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एम्स के लिए जमीन की कमी की गंभीर समस्या का हल सुझाया है। उन्होंने लोकसभा में सुझाव दिया है कि बदरपुर के पावर हाउस की खाली पड़ी लगभग 400 एकड़ जमीन पर एम्स का नया अस्पताल खोला जाए। उन्होंने इस खाली पड़ी जमीन पर कॉलेज और स्टेडियम बनाने की मांग भी सरकार से की है और वहां चल रहे केंद्रीय विद्यालय को जारी रखने का आग्रह किया। आज लोकसभा में यह मामला उठाते हुए बिधूड़ी ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अस्पताल है लेकिन इस अस्पताल को अब जमीन की कमी के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि अस्पताल में कई विभागों के लिए अब स्थान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को एम्स में इलाज के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल मरीजों की इस भीड़ को झेलने में भी असमर्थ हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो एम्स में जमीन का अभाव है और दूसरी तरफ बदरपुर में एनटीपीसी के बंद हो चुके पावर हाउस की लगभग 400 एकड़ जमीन सरकार के पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर एम्स का विस्तार किया जाए और यहां अस्पताल खोला जाए। इससे यहां के लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी और एम्स की जमीन की समस्या का भी निवारण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शालीमार बाग के विभिन्न ब्लॉकों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, लेन सुधार करने और जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य जारी हैं। साथ ही अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, वॉटर एटीएम, जिम, सीसीटीवी कैमरे, स्विमिंग पूल और नए पार्क जैसी सुविधाओं का विकास भी तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सेवाओं से युक्त एक आदर्श मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री आज शंकराचार्य मार्ग स्थित आश्रम में आयोजित श्री विद्या महायज्ञ में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन आयोजन में बच्चों की उत्साहपूर्ण सहभागिता विशेष रूप से प्रेरक रही। उन्होंने कहा कि जब हमारी नई पीढ़ी धर्म, सेवा और संस्कारों से जुड़ती है, तभी समाज की जड़ें और अधिक मजबूत होती हैं। आश्रम में सेवा में संलग्न सभी वरिष्ठजनों की निष्ठा और समर्पण अनुकरणीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां ललिता महतारी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमें समाज, राष्ट्र तथा गौ माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और सेवा भाव से करते रहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि गौ माता को भोजन कराना केवल एक कर्म नहीं, यह उस सोच का प्रतिबिंब है जहां जीवन के हर रूप के प्रति आदर और संरक्षण का भाव निहित है। यही भावना हमारे सनातन सांस्कृतिक मूल्यों की आधारशिला है, जहां सेवा को आस्था से जोड़ा जाता है और परंपरा को समाज-निर्माण से। गौ सेवा के इस भाव के साथ हम एक संवेदनशील, संतुलित और संस्कारयुक्त समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

संसद में साबित हुई केजरीवाल सरकार की छात्रों से की गई कारगुजारी : वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी शिक्षा व्यवस्था पर जमकर आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संसद में भी केजरीवाल सरकार की छात्रों के साथ की गई कारगुजारी प्रमाणित हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार कहती रही है कि दसवीं का परीक्षा फल सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए केजरीवाल सरकार लगभग हर कमजोर छात्र को नौवीं में फेल कर देती थी। उन्होंने कहा कि वीरवार को संसद पटल पर रखे आंकड़ों ने भाजपा के आरोपों को प्रमाणित कर दिया है। सचदेवा ने कहा कि आप संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था के दावे खोखले हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के जवाब ने भाजपा के कथन को सही साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के पेश आंकड़ों के अनुसार 2020-21 एवं 2021-22 जो दो कोविड़काल वर्ष थे में 31541 एवं 28548 छात्र नौवीं कक्षा में फेल हुए और उनमें से केवल 11322 एवं 10598 छात्रों ने आगे ओपन स्कूल से शिक्षा जारी रखी। शेष 39519 छात्रों ने शिक्षा आगे चालू ही नहीं रखी। इसी तरह 2022-23 कुल 88421 कक्षा 9वीं में फेल हुए उनमें से केवल 29436 छात्रों ने ही ओपन स्कूल से आगे शिक्षा जारी रखी। सचदेवा ने कहा कि 2023-24 जब आतिशी मार्लेना शिक्षा मंत्री बन गईं थी 9वीं में फेल होने वाले छात्रों की संख्या एक लाख का आंकड़ा पार कर 101344 पर जा पहुंची और उनमे से केवल 7794 छात्रों ने पढ़ाई ओपन स्कूल से जारी रखी और गत वर्ष 2024-25 में 70296 छात्र फेल हुए जिनमे से केवल 11974 ने ओपन स्कूल से शिक्षा आगे जारी रखी।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा पसंद का परीक्षा केंद्र : यूपीएससीसी

नई दिल्ली (एजेंसी)। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने सभी परीक्षाओं के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता (40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता) वाले अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का केंद्र आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों तक उनके पहुंचने को सुगम करना है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि इन अभ्यर्थियों को आने-जाने में अक्सर होने वाली समस्याओं और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में बताई गई उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र ही आवंटित किए जाएंगे। करना पड़ता था कठिनाइयों का सामना यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के परीक्षा केंद्रों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि दिल्ली, कटक, पटना, लखनऊ जैसे कुछ केंद्रों की क्षमता बहुत जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि वहां आवेदकों की संख्या काफी अधिक होती है। उन्होंने कहा कि इससे दिव्यांग अभ्यर्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उन्हें फिर ऐसे केंद्र चुनने पड़ते थे जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होते। मुझे खुशी है कि इस निर्णय से अब प्रत्येक दिव्यांग अभ्यर्थी को उनकी पसंद का केंद्र मिल सकेगा, जिससे यूपीएससी परीक्षाओं में शामिल होने के दौरान उन्हें अधिकतम सुविधा और सहजता सुनिश्चित होगी।

डीडीए ने सैनिक फार्म में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सैनिक फार्म में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ शुक्रवार सुबह बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीडीए अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण को हटाते हुए एक कोठी सहित कई संरचनाओं पर बुलडोजर चलाए गए। प्राधिकरण का कहना है कि सैनिक फार्म में अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे थे, जिनके खिलाफ अदालतों में भी कई मामले लंबित हैं। डीडीए ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हालांकि स्थानीय निवासियों ने कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि वर्षों से घरों में रह रहे लोगों को बिना पूर्व सूचना बेघर कर दिया गया। कुछ निवासियों ने बताया कि सुबह चार बजे उन्हें घरों से बाहर निकलने को कहा गया और बच्चों व बुजुर्गों को ठंड में खुले आसमान के नीचे खड़ा होना पड़ा। स्थानीय निवासी निहाल खटाना ने कहा कि वे 30-40 वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं और संपत्ति कर सहित सभी सरकारी करों का भुगतान करते आए हैं। उनके अनुसार, अचानक कार्रवाई से सैकड़ों लोग बेसहारा हो गए हैं। डीडीए का कहना है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा प्राथमिकता है, वहीं स्थानीय निवासियों ने पुनर्वास और उचित प्रक्रिया की मांग उठाई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ईसी की 1280 वीं बैठक: 28 फरवरी को डीयू के 102 वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उप राष्ट्रपति

-डीयू के आर्ट्स फ़ैकल्टि में बनेगा सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज़, आर्ट्स फैकल्टी में नवीनीकृत हाल का नाम होगा वंदे मातरम् हाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1280 वीं बैठक का आयोजन शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के आरंभ में अपने संबोधन में कुलपति ने बताया कि 28 फरवरी 2026 को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय की 102 वें दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि उससे पहले 30 जनवरी को नशा मुक्ति अभियान को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी माननीय उपराष्ट्रपति डीयू में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।

बैठक के दौरान चीफ इंजीनियर अशोक सैनी ने विश्वविद्यालय में जारी निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों पर जानकारी प्रस्तुत की। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। इनमें से अधिकतर निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान कुलपति ने प्रस्ताव रखा कि आर्ट्स फैकल्टी में स्थित कन्वेंशन हाल का नाम नवीनीकरण के बाद वंदे मातरम् हाल रखा जाए। सभी ईसी सदस्यों ने इस बारे अपनी सहमति जताई। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज़ बनाने के लिए बनी कमेटी की सिफारिशों पर विचार के उपरांत उन्हें भी मंजूरी दे दी गई है। यह सेंटर डीयू की आर्ट्स फ़ैकल्टि में बनाया जाएगा।

इसके साथ ही कुलपति ने बताया कि 12 से 14 फरवरी, 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि यह देश का सर्वोत्तम समारोह हो। डीयू ईसी की बैठक के आरंभ में डीयू कुलसचिव डॉ विकास गुप्ता ने पिछली ईसी बैठक के मिनट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। गत 05 दिसंबर को आयोजित हुई डीयू एकेडमिक कार्उंसिल की बैठक में की गई सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत उन्हें भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शून्य काल के दौरान सदस्यों ने अपने अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। बिल्डिंग कमेटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की वाइस रीगल लॉज बिल्डिंग के पास एक ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाने के प्रपोजल को मंजूरी दी है जिसकी अनुमानित लागत.2,32,08,537 रुपए है। डीयू ईसी ने इस प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रखा गया 1651.42 करोड़ रुपए का बजट अनुमान

डीयू ईसी की इस बैठक में फाइनेंस कमेटी की 09 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई बैठक में की गई सिफ़ारिशों पर विचार करने के उपरांत उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के संसोधित बजट अनुमान और वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान पर भी विचार करने के उपरांत उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। संसोधन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान 1664.74 करोड़ रुपए से घटाकर अब 1312.33 करोड़ रुपए रखा गया है इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1651.42 करोड़ रुपए का बजट अनुमान पेश किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के ढाका कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स हॉस्टल के लिए इस्तेमाल होगी खाली जमीन

दिल्ली विश्वविद्यालय ने ढाका कॉम्प्लेक्स में कुल 3.7 एकड़ खाली जमीन को गर्ल्स हॉस्टल के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ईसी में एजेंडा प्रस्तुत करते हुए कुलसचिव डॉ विकास गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ढाका कॉम्प्लेक्स वाली अपनी जमीन को साल 1975 में दिल्ली स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ़ कॉरेस्पोंडेंस कोर्स/स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग (एसओएल) और वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट (वीपीसीआई) को अलॉट की थी। शर्त यह थी कि अगर 3 साल के अंदर निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो उसके बाद अलॉट की गई जमीन के पोजेशन का रिव्यू किया जाएगा।

अलॉट की गई जमीन में से दिल्ली स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क को 1.70 एकड़, स्कूल ऑफ़ कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज/एसओएल को दो एकड़ और वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट को तीन एकड़ आवंटित की गई थी। एसओएल ने अलॉट की गई जमीन का पूरा इस्तेमाल किया था, जबकि वीपीसीआई ने सिर्फ़ एक एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया और दो एकड़ जमीन इस्तेमाल नहीं हुई है। वीपीसीआई की खाली जमीन के साथ गर्ल्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स भी है। गर्ल्स स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए, वीपीसीआई की दो एकड़ जमीन और दिल्ली स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क की 1.7 एकड़ खाली जमीन (कुल 3.7 एकड़ खाली जमीन) को गर्ल्स हॉस्टल के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज़ बढ़ाएगा भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और रीति-रिवाजों पर विचार-विमर्श का दायरा: प्रो. योगेश सिंह

दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज़ बनाने के लिए बनी कमिटी की सिफारिशों पर विचार के उपरांत इसे मंजूरी दे दी गई है। यह सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ़ आर्ट्स का हिस्सा होगा। डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि यह सेंटर उड़िया भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और रीति-रिवाजों पर आने वाली पीढ़ियों और आज के नज़रिए से भी विचार-विमर्श का दायरा बढ़ाएगा ताकि इस ज्ञान के क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझा जा सके। यह सेंटर करिकुलम डिज़ाइन और एकेडमिक प्रोग्राम को लागू करने के साथ-साथ डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए विद्यार्थियों के एनरोलमेंट को आसान बनाने के लिए फैकल्टी ऑफ़ आर्ट्स का हिस्सा होगा।

कुलपति ने बताया कि इस सेंटर द्वारा सेमेस्टर मोड में दो साल के पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के तौर पर उड़िया में एमए शुरू की जाएगी। एनईपी 2020 के अनुसार, चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के हिसाब से एक साल के पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में आगे के तरीके ऑपरेशनल ज़रूरत के आधार पर बाद में तय किए जाएँगे। उड़िया स्टडीज़ के लिए एक नया सेंटर बनाने का मकसद पोस्टग्रेजुएट लेवल पर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के साथ ही उड़िया स्टडीज़ में डॉक्टरेट (पीएचडी) और पोस्टडॉक्टरल रिसर्च, दोनों लेवल पर अच्छी क्वालिटी की रिसर्च को बढ़ावा देना। इसके साथ ही इस सेंटर का उद्देश्य सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के साथ-साथ पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम देना और अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के ज़रिए अंडरग्रेजुएट लेवल पर उड़िया स्टडीज़ में जेनेरिक इलेक्टिव देना भी है ताकि समृद्ध उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति को सही नज़रिए से लोकप्रिय बनाया जा सके। ऐतिहासिक नज़रिए से उड़िया भाषा, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर, डांस, परंपराओं, फिलॉसॉफिकल प्रैक्टिस, सुधारवादी आंदोलनों, लोकगीतों, मौखिक परंपराओं के विकास का पता लगाने का काम भी यह सेंटर करेगा।

पुल से 20 फुट नीचे गिरे डंपर में लगी आग में जिंदा जले ड्राइवर व हेल्पर

नीचे गिरते ही डंपर का डीजल टैंक फटा, जलकर कंकाल बने दोनों शव

संवाददाता

नूंह। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार को तेज रफ्तार डंपर पुल की दीवार तोड़ता हुआ 20 फुट नीचे नाले में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि डंपर के नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। जिसमें ड्राइवर और हेल्पर की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को डंपर से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लगभग छह बजे डंपर फिरोजपुर झिरका से दिल्ली की तरफ जा रहा था। डंपर जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गांव गुर्जर नगला के पास पहुंचा तभी अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार होने के कारण डंपर पुल की दीवार तोड़ते हुए नीचे गिर गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नीचे गिरते ही डंपर का डीजल का टैंक फट गया और तेज धमाके के साथ आग लग गई। हादसा देखकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और ड्राइवर हेल्पर को बाहर निकालने का प्रयास किया। चालक और हेल्पर दोनों डंपर में आग की लपटों में आ गए। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक ड्राइवर और हेल्पर जिंदा जल चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी का हेल्पर बुरी तरह जल गया था, जिसका केवल कंकाल ही बचा हुआ था। हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अलआफिया अस्पताल मांडीखेड़ा भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक ड्राइवर की पहचान रंजीत पुत्र रमजु निवासी निमली जिला अलवर राजस्थान के रूप में हुई है, लेकिन अभी हेल्पर की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस हेल्पर की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

विश्वविद्यालयों की भूमिका अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं: प्रो. वी.के मल्होत्रा

जीयू में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का समापन

संवाददाता

गुरुग्राम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट तथा कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएमयू के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय 5वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हो गया। एआई के युग में उद्यमिता, स्थिरता और सामाजिक नवाचार के प्रतिमान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो. वी.के. मल्होत्रा, चेयरमैन एम.पी. स्टेट फूड कमीशन भोपाल रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. संजय कौशिक, मुख्य संरक्षक डॉ. संजय अरोड़ा, विशिष्ट अतिथि डॉ. हरप्रीत, आदि ने दीप प्रज्ज्वलन कर समापन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

इस दौरान सम्मेलन के लिए 156 से अधिक रिसर्च पेपर प्राप्त हुए। सम्मेलन में एआई के युग में उद्यमिता, स्थिरता और सामाजिक नवाचार के प्रतिमान के बारे में अपने

विचार प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लगभग 300 से अधिक शोध विद्वान, संकाय सदस्य, छात्र और प्रमुख अधिकारी एक साथ आए। गुरुग्राम विवि के प्रबंधन विभाग की डीन डॉ. अमरजीत कौर ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लक्ष्यों के बारे में सभी को जानकारी दी। 16 देशों से आए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और उद्यमियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. वी.के. मल्होत्रा, ने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उन्हें नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक उत्तरदायित्व का केंद्र बनना होगा। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा कि भविष्य उन्हीं का है जो तकनीक को समाज के विकास से जोड़कर देखते हैं। एआई केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामूहिक प्रगति का साधन है। उन्होंने कहा कि एआई को उद्यमिता में सही दिशा और नीति के साथ जोडना आवश्यक है उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि स्टार्टअप का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के लिए समाधान पैदा करना होना चाहिए। एआई हमें वही दृष्टि देता है।

सिकंदरपुर में छापेमारी में दो क्विंटल प्लास्टिक जब्त, 25 हजार के चालान

संवाददाता

गुरुग्राम। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम गुरुग्राम एवं राइजिंग फाउंडेशन के सहयोग से गांव सिकंदरपुर में स्वच्छता अभियान एवं सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान संयुक्त टीमों ने बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। इस अभियान में कुल दो क्विंटल छह किलो प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 25 हजार के चालान किए गए।

अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा नागरिकों में सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना था। निरीक्षण टीम ने पर्यावरण हित में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान करते हुए यह भी संदेश दिया कि यह निरीक्षण

अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण टीम में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्षेत्रीय अधिकारी गुरुग्राम (उत्तर) अंकाक्षा तंवर, सहायक पर्यावरण अभियंता कामेश, एमसीजी से सहायक स्वच्छता निरीक्षक भूपेंद्र व सहायक पर्यावरण अभियंता आरशि गहलावत शामिल रहे।

गुरुग्राम में लोक अदालत आज, निपटाएं अपने लंबित मामले

संवाददाता

गुरुग्राम। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम ने न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता और वाणी गोपाल शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम के दिशा-निर्देश अनुसार जिला न्यायालय में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम राकेश कादियान ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 27 जजों की बेंचेज गठित की गयी हैं, जिनमे नौ बेंचेज केवल ट्रैफिक चलान के निपटारों के लिए लगाई गई हैं। चेक बाउंस केसों के निपटारे के लिए 10 बेंचेज लगाई गई हैं। उप मंडल सोहना एवं पटौदी में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उप मंडल सोहना में एक बेंच और पटौदी में एक बेंच बनाए गए हैं। ट्रैफिक चालान के

भुगतान के लिए भी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क लगाई गयी है। यह हेल्प डेस्क कोर्ट के गेट नंबर-2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में लगी हुई है और एक कोर्ट परिसर में। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम ने आमजन से अपील की है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलों को लोक अदालत में रखें। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम में 0124-2221501 पर सम्पर्क कर सकता है। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों का निबटारा किया जा सकता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

गुरुग्राम जिला स्केटिंग चैंपियनशिप में रॉयल स्कूल के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

संवाददाता

गुरुग्राम। स्कूल स्पोर्ट्स एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ गुरुग्राम द्वारा आयोजित जिला स्केटिंग चैम्पियनशिप 2025 में रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वजीरपुर सेक्टर-95 के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विभिन्न श्रेणियों में पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता का आयोजन गुरु श्री जगराज सिंह साहने जी बैंक्ड स्केटिंग ट्रैक दौलताबाद, सेक्टर-103 गुरुग्राम में किया गया। चैम्पियनशिप में अंडर-12 में हर्षित, अनुज, अंडर-15 में अंकित व अंडर-8 में परी खेत ने स्वर्ण पदक जीते। अंडर-10 में सचिन व हितेन ने रजत पदक हासिल किए। अंडर-10 में ही विराट ने व अंडर-15 में सत्यम ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में पीटीआई योगेश सिंह, पीटीआई संजू जाट को उनके उत्कृष्ट प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए बेस्ट कोच का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन डा. विजय डुक्षसह एवं खेल प्रशिक्षकों ने सभी विजेता छात्रों और कोचों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। डा. विजय सिंह ने कहा कि विद्यालय में बच्चों को सर्व कला संपन्न बनाने काम किया जाता है। पढ़ाई के साथ खेलों में भी भविष्य है, इसलिए खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने खिलाड़ी छात्रों से कहा कि अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, सफलता उनके कदम चूमेगी।

रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना महत्वपूर्ण : राजीव रंजन

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लिए गुरुग्राम में अवेयरनेस वर्कशॉप

संवाददाता

गुरुग्राम। हरियाणा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने कहा कि प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा उद्योगों को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उद्योगों को कार्यबल सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

प्रधान सचिव राजीव रंजन शुक्रवार को गुरुग्राम के जीआईए हाउस स्थित सभागार में आयोजित एक दिवसीय अवेयरनेस वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। यह वर्कशॉप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एसईजेड एंटरप्राइजेज, एमएसएमई प्रतिष्ठानों तथा गुरुग्राम की विभिन्न इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों के लिए आयोजित की गई थी। राजीव रंजन ने वर्कशॉप में उपस्थित नियोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार

आधारित प्रोत्साहन योजना को एक अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में लागू किया गया है। विकसित भारत पहल के अनुरूप तैयार की गई यह योजना देशभर में समावेशी एवं स्थायी रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक सिद्ध होगी। इस दौरान उन्होंने योजना के संदर्भ में नियोक्ताओं से सुझाव भी मांगे। प्रधान सचिव ने यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगारों को प्रोत्साहित करेगी तथा विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। योजना के दो प्रमुख भाग निर्धारित किए गए हैं।

भाग ए पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

पीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, इस भाग में एक महीने का ईपीएफ वेतन, अधिकतम 15,000 रुपये दो किश्तों में दिया जाएगा। एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी बाद में इसे निकाल सकेगा।

यह भाग सभी सेक्टरों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगा, जिसमें विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

सरकार कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक नियोक्ताओं को अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण सेक्टर के लिए प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त प्रमोद सिंह, इंद्राज सिंह एवं नितेंदु मिश्रा, जीआईए के पूर्व प्रेजिडेंट जे एन मंगला, वर्तमान प्रेजिडेंट सुमित राव, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक गौरव लाठर, डीईओ रंजीत रावत, डीएलओ राजेश सांगवान, एईओ ज्योति सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

मेयर का नैनवाल में लगा जनता दरबार, ग्रामीणों ने विकास कार्यों की रखी मांग

-मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव के साथ नगर निगम के अधिकारी रहे मौजूद
-ग्रामीणों की मांग पर मेयर ने दिए त्वरित कार्रवाई के आदेश

संवाददाता

गुरुग्राम। नगर निगम मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव की ओर से आयोजित आपकी मेयर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव नैनवाल में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने विकास कार्यों से जुड़ा एक मांगपत्र मेयर के समक्ष रखा। इस दौरान उनके साथ डीएमसी अपूर्व चौधरी, एसडीओ अमन राठी सहित नगर निगम की सभी शाखाओं के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जनता दरबार में पहुंचकर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। मेयर डा. इंद्रजीत कौर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानना और उनका त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि पुराने दिन लद गए जब शिकायतों के कागज फाइलों में दबकर रह जाते थे और आमजन को लंबे समय तक परेशान रहना पड़ता

था। अब अधिकारी स्वयं गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन पर तय समय पर कार्रवाई अमल में लाएंगे। जनता दरबार के दौरान ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्यों की मांगों को लेकर मेयर को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से पेयजल, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मेयर को अवगत करवाया कि गांव में मंदिर के पास

पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल, टेनिस कोर्ट के पास निगम की भूमि पर चार दीवारी करवाने, सत्ती माता मंदिर तक जाने वाले रास्ते का निर्माण, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की मांग मुख्य रुप से रही। ग्रामीणों की मांग सुनने के बाद मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी का मौका निरीक्षण करके जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें। जिन कामों को तत्काल किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए। अन्य मांगों का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाए। इस मौके पर संपत सिंह, होराम, रितेश, बलराज, कृष्ण, सुरेंद्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त का स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा अहम योगदान : डा. घमंडीलाल अग्रवाल

संवाददाता

गुरुग्राम। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कवियों, साहित्यकारों, कहानीकारों का भी काफी योगदान रहा है। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि होने का सौभाग्य प्राप्त है। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। उनकी जयंती प्रति वर्ष कवि दिवस के रुप में मनाई जाती है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए साहित्यकार डा. घमंडीलाल अग्रवाल ने कहा कि उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तरप्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उनका रुझान बाल्यकाल से ही कविता रचना की ओर था। वह तत्कालीन साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बड़े प्रभावित थे। वर्ष 1912-13 में उन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जिससे उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। उन्होंने वर्ष 1932 में यशोधरा की रचना भी की। 1941 को सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी-लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। देश आजाद होने के बाद वह राज्यसभा के 12 वर्ष तक सदस्य भी मनोनीत रहे। केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया था। डा. अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपने जीवनकाल में 2 महा काव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत एवं कई नाटिकाओं की रचना भी की थी। उन्होंने अपने युग की समस्याओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस के समक्ष रखा था। उनके काव्य में राष्ट्रीयता और गांधी

विकास परियोजनाओं को लेकर आपसी समन्वय से कार्य करें सभी विभाग: राव नरबीर सिंह

नीचे गिरते ही डंपर का डीजल टैंक फटा, जलकर कंकाल बने दोनों शव

संवाददाता

गुरुग्राम। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिला के विकास व नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। साथ ही जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां संभव हो पेड़ों को नहीं काटा जाए और अधिकतम संख्या में उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने यह बात शुक्रवार को गुरुग्राम के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में जिला में जारी विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा व अंतर विभागीय विषयों को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने जीएमडीए द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में सडक़ों के सुधारीकरण के बारे में

जानकारी ली। बैठक में जीएमडीए अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-58/61, 59/61 डिवाइडिंग रोड, सेक्टर-28/43 रोड, सेक्टर-58 से 67, एमजी रोड तथा 62/65 रोड पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक निर्माण के दौरान बिजली के खंभे अड़चन बने हुए हैं। मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने और फरवरी माह के अंत तक सभी खंभों के स्थानांतरण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। वन विभाग से जुड़े मामलों पर मंत्री ने कहा कि कई सडक़ों पर निर्माण कार्य बाधित होने के बावजूद पेड़ों को अनावश्यक रूप से न काटा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो पेड़ों को बचाया जाए और विकल्प तलाशे जाएं। राव नरबीर सिंह ने जिला में ड्रेनेज की सफाई के बारे में भी विभागवार समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग की सरफेस ड्रेनों की सफाई नियमित रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही जहां नई ड्रेनेज कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसे मानसून से पहले ही पूरा करने के निर्देश दिए गए। नरसिंहपुर के पास प्रस्तावित कल्वर्ट निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। जीएमडीए को लैग-4 का कार्य मई माह के अंत तक पूरा करने के लिए कहा गया।

सडक़ों के रख-रखाव और एक्सीलेटर संचालन पर चर्चा

उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के एक्सीलेटर शुरू करने, 24 मीटर सडक़ों की मरम्मत और नियमित रख-रखाव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने संबंधित विभागों को सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही नई सडक़ परियोजना का काम शुरू करने से पहले फुटपाथ और ड्रेनेज का कार्य पूरा होना चाहिए और निर्माण करने वाली एजेंसी को भुगतान करने के लिए संबंधित आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों की सहमति ली जाए।

राव नरबीर सिंह ने आदेश दिए कि सभी ग्रीन बेल्ट सडक़ों के लेवल से नीचे रखी जाएं, सभी स्लिप रोड रेड लाइट से 50 मीटर पहले बनाई जाएं। उन्होंने सडक़ों की डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड को बढ़ाकर पाँच वर्ष करने की बात भी कही, ताकि निर्माण गुणवत्ता में सुधार हो।

डिजिटल अरेस्ट ठगी से लाखों परिवारों के जीवन में अंधकार

मनोज कुमार अग्रवाल

आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करें, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर को सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है।

लाखों लोगों व परिवारों के जीवन भर की कमाई को डिजिटल अरेस्ट के जरिए लूट कर उनके जीवन में अंधेरा कर दिया गया। यह कैसी विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, की साल से यह सिलसिला जारी है तब सरकार और जिम्मेदार सिस्टम की नींद खुली है और अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर।

इन दिनों देश में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं. सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के कारण बुजुर्गों बड़ी संख्या में ठगी का शिकार हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट मामलों पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि इस मामले में अदालत जरूरी निर्देश जारी करेगी. न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हर हैरानी की बात है कि देश में पीड़ितों से लगभग 3000 करोड़ रुपये डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगे जा चुके हैं. यह सब हमारे देश में ही हो रहा है. अगर हम इस मामले में ठोस और सख्त आदेश नहीं देंगे तो समस्या और गंभीर हो जाएगी.

आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करें, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर को सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन-देन को गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निस्संदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें। दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को

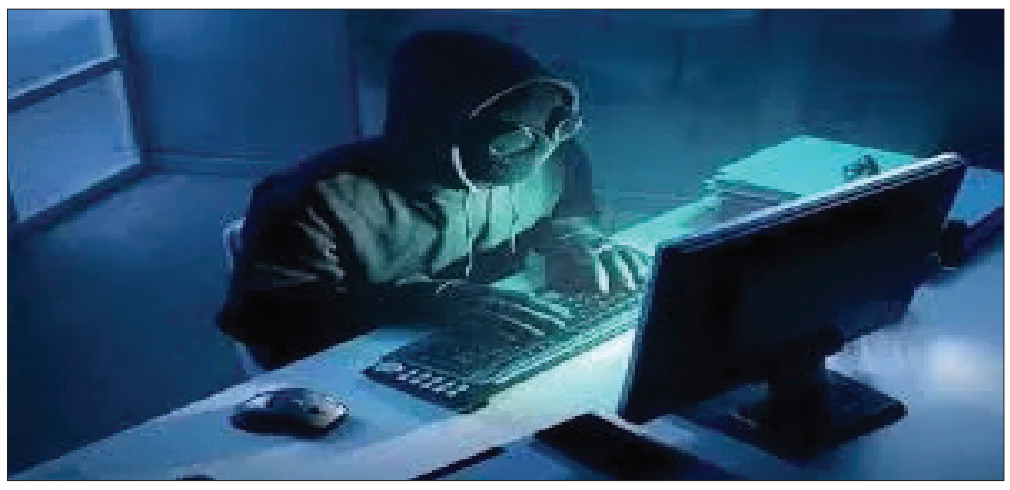

स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों-टुकड़ों में जांच सीमा पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है दरअसल, साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिये भोले-भाले लोगों व बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। वे कानून प्रवर्तन अधिकारी पुलिस और जज बनकर मोटी रकम देने के लिये उन्हें ब्लेकमेल और आतंकित करते हैं।हालांकि अदालत ने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक अलग यूनिट की स्थापना की है और इस मामले से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है. साथ ही डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं. डिजिटल अरेस्ट को लेकर हुई सुनवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी. केंद्र सरकार की ओर से पेश दलील के सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामला काफी गंभीर है और इस मामले में अदालत उचित आदेश पारित करेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के पत्र लिखकर बताया था कि 1 से 16 सितंबर के बीच उनसे 1.5 करोड़ रुपए की ठगी सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो तो कभी न्यायपालिका के अधिकारी बनकर की गयी. धोखेबाजों ने फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे वसूलने का काम किया. इतना ही नहीं उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश दिखाए. मामला सामने आने के बाद अंबाला में दो एफआईआर दर्ज की गयी. जांच में पाया गया कि वरिष्ठ नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने के लिए संगठित गिरोह काम कर रहा है. अदालत ने 17 अक्टूबर को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की और केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब देने को कहा. अदालत ने इस मामले में अटार्नी जनरल से भी सुझाव लेने का आदेश दिया.

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये कीठगी के बाद अदालत ने इस व्यापक समस्या का स्वतः संज्ञान लिया। उन्हें धमकाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति है कि साइबर अपराधी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल रहे हैं।तभी शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, देश की केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की तह तक तुरंत पहुंचना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग को भी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कहा गया है। निश्चित रूप से कोर्ट की सार्थक पहल के बाद यदि ये सभी उपाय सिरे चढ़ते हैं तो इस गंभीर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। कोर्ट ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय एजेंसी बिना किसी भय या पक्षपात के जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इसमें राज्य सरकारों की सक्रियता व सजगता भी सीबीआई को अपराध की तह तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकती है। यह भी जरूरी है कि एजेंसी की कार्रवाई में लालफीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। इसके साथ ही नागरिकों को भी ऐसे अपराधों के प्रति सजग रहना होगा। जागरूकता सतर्कता उन्हें अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचा सकती है। ऐसी किसी कॉल के आने पर उन्हें रुककर विचार करना चाहिए और हड़बड़ी में बैंक से जुड़ी कोई जानकारी देने से बचना चाहिए। ठग खुद को केंद्रीय एजेंसियों या पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ितों को फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी देते थे। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर उनसे बैंक खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 35 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आरोपी गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पकड़े गए हैं। राजनांदगांव की 79 वर्षीय शीला सुवाल को आरोपितों ने सीबीआई अधिकारी और जज बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से डराया। मनी लॉडिंग केस में फांसाने की धमकी दी। निर्दोष साबित करने रकम जज के खाते में ट्रांसफर करने को कहा। महिला ने उगों के बताए गए विभिन्न खातों में 79,69,047 रुपये ट्रांसफर कर दिए। एक अन्य मामले में ठगों ने फारेक्स व ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर व्यापारी को फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट का लिंक भेजा। पहले 15 हजार का छोटा मुनाफा देकर व्यापारी का विश्वास हासिल किया, फिर बड़े मुनाफे का लालच देकर 1,21,53,590 रुपये निवेश के नाम पर जमा कराए। दोनों मामलों में तीन आरापितों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में उप विदेशी कॉल सेंटरों की तरह काम करते हुए इंटरनेट कालिंग और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते थे। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध काल या डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियों पर विश्वास न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन को देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में सीबीआई की मदद करने के भी निर्देश दिए। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा कि साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पहले 3 नवंबर की सुनवाई में एससी ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट मामलों में लगभग 3 का पता चला है।

अभी तक डिजिटल अरेस्ट कर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है आज भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रहीं हैं जिनमे लोगों को मोबाइल काल पर तरह तरह से धमका कर पैसा ठगी किया जा रहा है लोग जीवन भर की खून पसीने की कमाई चंद मिनटों में गंवा कर सुसाइड करने के लिए विवश हो रहे हैं। सरकार को ऐसे अपरोक्ष हत्यारों ठगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संपादकीय

भारत और रूस की दोस्ती असीमित

कुल मिला कर द्विपक्षीय संबंध रूस के पक्ष में बेहद झुका हुआ है। उसका क्या समाधान पुतिन पेश करेंगे? उधर रूस और चीन के हित एक दूसरे के संपूरक बने हुए हैं, जबकि यह पहलू भारत के नजरिए एक समस्या है। नई दिल्ली आने से ठीक पहले व्लादीमीर पुतिन ने भारत- रूस के संबंध के बारे में अपना टेम्पलेट सामने रखा है। उन्होंने संदेश दिया कि वे भारत से वैसी ही 'असीमित दोस्तीइ चाहते हैं, जैसी उन्होंने चीन के स्थापित की है। पुतिन ने कहा- ह्यचीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हमने आर्थिक मुद्दों पर ठोस वार्ता कायम की है। भारत यात्रा के दौरान हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इनमें रूसी बाजार में भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाना भी शामिल है।

यही संदेश देने के लिए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत की। उन्होंने कहा- 'हमारा चीन के साथ असीमित सहयोग बना है। भारत के बारे में भी हमारा वही रुख है। रूस वहां तक जाने को राजी है, जहां तक भारत तैयार हो। पेस्कोव ने संकेतों में यह भी कहा कि भारत को रूस से अपने संबंध तय करने में अमेरिकी हस्तक्षेप का ख्याल नहीं करना चाहिए। उन्होंने एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली और सुखोई-57 लड़ाकू विमान भारत को बेचने की पेशकश की। उम्मीद जताई भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। मगर भारत में चिंता यह है कि ये रूसी मंशाएं पूरी हुईं, तो उसका खराब असर अमेरिका से रिश्तों पर पड़ेगा। फिर बढ़ते व्यापार घाटे की भारत की अपनी चिंताएं भी हैं।

भारत इस समय रूस को जितना निर्यात करता है, उससे लगभग 17 गुना ज्यादा आयात कर रहा है। इसके अलावा अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक भारत में प्रत्यक्ष रूसी निवेश महज 1.33 बिलियन डॉलर का हुआ, जबकि रूस में 12.8 बिलियन डॉलर का भारतीय निवेश हुआ है। तो कुल मिला कर द्विपक्षीय संबंध रूस के पक्ष में बेहद झुका हुआ है। उसका क्या समाधान पुतिन पेश करेंगे? दरअसल, रूस और चीन के हित संपूरक बने हुए हैं, जबकि यह पहलू भारत के नजरिए एक समस्या है। इस कारण भारत- चीन विवाद में रूस निष्पक्ष रुख लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। ये सारे वो पेच हैं, जिन्हें खोले बिना भारत और रूस की दोस्ती शायद असीमित रूप ना ले पाए।

चिंतन-मनन

सबसे बड़ा दरिद्र

सिंहगढ़ राज्य की सीमा के पास एक गांव सोनपुर में एक महात्मा अपने दो शिष्यों के साथ आ पहुंचे। वहां की शांति और हरियाली देख कुछ दिन वे वहीं ठहर गए। एक दिन महात्मा जी जब भिक्षा मांगने जा रहे थे, सड़क पर एक सिक्का दिखा, जिसे उठाकर उन्होंने झोली में रख लिया। दोनों शिष्य इससे हैरान थे। वे मन में सोच रहे थे कि काश सिक्का उन्हें मिलता, तो वे बाजार से मिठाई ले आते। महात्मा जी भांप गए। बोले-यह साधारण सिक्का नहीं है, मैं इसे किसी सुपात्र को दूंगा। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने सिक्का किसी को नहीं दिया। एक दिन महात्मा जी को खबर मिली कि सिंहगढ़ के महाराज अपनी विशाल सेना के साथ उधर से गुजर रहे हैं। महात्मा जी ने शिष्यों से कहा, वत्स! सोनपुर छोड़ने की घड़ी आ गई। शिष्यों के साथ महात्मा जी चल पड़े। तभी राजा की सवारी आ गई। मंत्री ने राजा को बताया कि ये महात्मा जा रहे हैं। बड़े ज्ञानी हैं। राजा ने हाथी से उतर कर महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। महात्मा जी ने झोले से सिक्का निकाला और राजा की हथेली पर उसे रखते हुए कहा, हे सिंहगढ़ नरेश, तुम्हारा राज्य धन-धान्य से संपन्न है। फिर भी तुम्हारे लालच का अंत नहीं है। तुम और पाने की लालसा में युद्ध करने जा रहे हो। मेरे विचार में तुम सबसे बड़े दरिद हो। इसलिए मैंने तुम्हें यह सिक्का दिया है। राजा इस बात का मतलब समझ गए। उन्होंने सेना को वापस चलने आदेश दिया।

पोक्सो मामलों की बढ़ती लंबितता भारत के समक्ष बढ़ता गंभीर संकट

कांतिलाल मांडोत

भारत एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और नैतिक मूल्यों वाला देश माना जाता है जहाँ बच्चों को देवतुल्य समझने की परंपरा रही है। किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक सत्य है कि आज इसी देश में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि इन मामलों का निपटारा वर्षों तक अधर में लटका रहता है। पोक्सो यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके ठीक विपरीत तस्वीर पेश करती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में पोक्सो के 35 हजार से अधिक मामले वर्षों से लंबित चल रहे हैं और न्याय की प्रक्रिया पीड़ितों व उनके परिवारों के लिए एक असहनीय इंतजार बन गई है।2023 तक लंबित मामलों का जो विवरण सामने आया है, वह किसी भी समाज और शासन के लिए चिंता का गंभीर संकेत है। उत्तर प्रदेश में 10,556 मामले लंबित हैं जो देश में सबसे अधिक हैं। महाराष्ट्र 7,962 लंबित मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में 1,910, मध्यप्रदेश में 1,736, छत्तीसगढ़ में 375 और राजस्थान में 224 मामले अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। बिहार में 1,079, झारखंड में 415, पंजाब में 152, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों में 101, चंडीगढ़ में 16 और उत्तराखंड में 374 मामलों की लंबितता भी यही सिद्ध करती है कि न्यायिक प्रक्रिया के बोझ ने पीड़ितों के लिए न्याय की राह लंबी और कठिन बना दी है। यह स्थिति बताती है कि देश में पोक्सो कानून का उद्देश्य जितनी तेजी से पूरा होना चाहिए था, उससे बहुत दूर है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल ने बताया है कि देश में कुल 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं जिनमें से 400 कोर्ट विशेष रूप से पोक्सो मामलों के लिए बनाए गए हैं। इन अदालतों ने अब तक 3.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है जो निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, लेकिन उसके बावजूद हजारों मामले अभी भी अधूरे पड़े हैं। यह दशार्ता है कि केवल अदालतों की संख्या बढ़ा देना समाधान नहीं है। न्याय प्रक्रिया में पुलिस, अभियोजन, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच, गवाही और साक्ष्य संकलन जैसे कई चरण होते हैं और इनमें होने वाली देरी पोक्सो मामलों की लंबितता को बढ़ाती रहती है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में हर तीन मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार बनता है और हर आठ मिनट में एक पोक्सो का मामला दर्ज होता है। इन आंकड़ों में बीते दो वर्षों के भीतर ही तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है जो सामाजिक व प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चेतावनी का इशारा है। 2021 से 2025 के बीच कुल 1,31,692 पोक्सो मामले दर्ज किए गए। वहीं सबसे कम मामले मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में सामने आए हैं।

एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि कई मामलों में अपराध की प्रकृति इतनी संवेदनशील होती है कि बच्चे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जिसमें कहा गया कि किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और उसे पैसे देकर यौन संबंध का प्रस्ताव देना भी पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। यह फैसला यवतमाल जिले की घटना पर आया जिसमें एक 13 वर्षीय बच्ची से आरोपी ने दो बार यौन इरादे से संपर्क किया था। अदालत ने आरोपी को सश्रम कैद की सजा सुनाई। यह फैसला स्पष्ट करता है कि अदालतें कानून की भावना के अनुरूप सख्त दृष्टिकोण अपना रही हैं, लेकिन मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि और उनके निपटारे में देरी स्थिति को गंभीर बनाती जा रही है। लंबित मामलों का सबसे बड़ा कारण पुलिस जांच की धीमी गति, मेडिकल व फोरेंसिक रिपोर्ट में देर, गवाहों का न मिल पाना, पीड़ित परिवारों का दबाव में आ जाना और अदालतों में पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। कई बार परिवार सामाजिक भय के कारण बयान देने से पीछे हट जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और अधिक गंभीर होती है जहाँ पीड़ितों को न्याय पाने के लिए सामाजिक प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है।

कर्ज, कर और कुशासन का त्रिकोण!

सोनम लववंशी

हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दिशा जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ पिछले तीन वर्षों की सरकारी कार्यशैली राज्य की पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ती दिखाई देती है। 11 दिसंबर 2025 को सुक्खू सरकार अपने तीन वर्ष पूरे कर रही है, किंतु इस दौरान एक पहले से संतुलित और स्थिर राज्य ऐसा ढलान महसूस कर रहा है जिसकी कल्पना भी हिमाचल जैसे शांत प्रदेश के लोगों ने न की थी। वित्तीय संकट, अव्यवस्थित नीतियाँ, ध्वस्त प्रशासनिक ढांचा, बढ़ती बेरोजगारी, आपदा प्रबंधन की विफलता और उद्योगों का पलायन। इन सभी ने मिलकर हलचल भरी स्थिति पैदा कर दी है जिस पर अब न केवल विपक्ष, बल्कि आम नागरिक भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी तक पहुँच चुकी है, जबकि 15-29 आयु वर्ग में स्थिति भयावह दिखती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य का हर तीसरा युवा नौकरी से वंचित है। अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में युवा बेरोजगारी 29.6 प्रतिशत दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 14.6 प्रतिशत से दुगुनी रही। यह आँकड़ा सिर्फ बेरोजगारी नहीं दशार्ता, बल्कि यह उस टूटते विश्वास का दस्तावेज बनता जा रहा है जिसके सहारे युवाओं ने '5 लाख नौकरियों' जैसी घोषणाओं को एक उम्मीद की तरह स्वीकार किया था। राजनीतिक आश्वासन जितनी आसानी से दिए गए, उतनी ही तेजी से खोखले साबित हुए और अब इन्हें युवा पीढ़ी राजनीतिक भाषणों की एक औपचारिक रस्म के रूप में देखने लगी है।

दरअसल राज्य की औद्योगिक स्थिति भी लगातार कमजोर हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में बिजली दरों में तेज वृद्धि देखने को मिली। ऐसी फैक्ट्रियों का बिजली बिल जो पहले लगभग 25 लाख रुपये आता था, अब 50 लाख रुपये से भी ऊपर पहुँच गया है। ऊर्जा लागत में इस असंतुलन ने उद्योगपतियों का मनोबल तोड़ दिया है और वे क्रमशः अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं जहाँ नीतियाँ स्थिर और उद्योग-अनुकूल मानी जाती हैं। यह पलायन हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रहार कर रहा है। रोजगार घट रहा है और राजस्व में गिरावट आ रही है। पर्यटन और कृषि पर अधिक निर्भर रह चुके हिमाचल ने बीते वर्षों में औद्योगिकीकरण की दिशा में एक स्थिर आधार बनाने की कोशिश की थी, किंतु वर्तमान परिस्थितियों ने उस बनती संरचना को लगभग ध्वस्त कर दिया है। वित्तीय अव्यवस्था का हाल यह है कि सरकार अपनी कर्ज सीमा पूरी कर चुकी है। वर्ष 2025 में पहले से लिए गए 7,200 करोड़ रुपए के भारी कर्ज के बाद और 350 करोड़ रुपए की माँग नई दिशा दिखाने के बजाय इस बात का प्रतीक बनती है कि विकास योजनाएँ ठप हैं और पूरा ढांचा कर्ज पर निर्भर होता जा रहा है। करोड़ों की पुनरावृत्ति जिस सहजता से हो रही है, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार के पास राजस्व बढ़ाने की ठोस रणनीति नहीं है। नीतिगत अनिर्णय ने राज्य की आर्थिक रीढ़ कमजोर कर दी है और जनता पर टैक्स बढ़ाकर बोझ डाला जा रहा है। दूध पर 0.10 पैसे का सेस, बिजली पर पर्यावरण सेस, डीजल की ऊँची कीमतें और 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का समाप्त होना। इन सबने मध्यवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है।

चुनावी वादों का हश्र भी जनता के सामने खुल चुका है। महिलाओं के लिए 1,500 रुपए मासिक भत्ता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 लाख नौकरियों जैसे वादे अब तक लागू न हो सके। स्वयं सूबे की सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार किया कि 'फंड उपलब्ध नहीं है,' जो यह दशार्ता है कि गारंटियाँ बिना वित्तीय विश्लेषण और बिना दीर्घकालिक योजना के घोषित की गई थीं। इस स्वीकारोक्ति के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की राजनीतिक विश्वसनीयता को गंभीर चोट पहुँची है। इतना ही नहीं इन तीन वर्षों में अपराध और नशा तस्करी की स्थिति तेजी से बिगड़ी है। हिमाचल का शांत पहाड़ी क्षेत्र अब 'ड्रग कॉरिडोर' के रूप में चर्चा में आ रहा है। पिछले तीन वर्षों में 5,000 से अधिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनपीडीएस) के मामले दर्ज हुए, जबकि पूरे प्रदेश में केवल 5 नशामुक्ति केंद्र हैं। यह संख्या समस्या की गंभीरता की तुलना में अत्यंत कम है। नशे का विस्तार न केवल कानून व्यवस्था की कमजोरी दिखाता है, बल्कि यह युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य, सामाजिक ढाँचे और परिवारों की स्थिरता को गहरी क्षति पहुँचा रहा है। सूबे की आपदा प्रबंधन की स्थिति भी किसी परीक्षा में असफल छात्र जैसी दिखती है। 2025 में कमजोर पहाड़ियों पर अवैध निर्माण, न्यायालयों की चेतावनियों की अनदेखी और खराब प्रशासनिक योजना के कारण 300 से अधिक लोगों की जान गई और लगभग 2,600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। केंद्र सरकार द्वारा जारी 2,006 करोड़ रुपए की राहत राशि का उपयोग भी सुस्त प्रशासनिक कार्रवाइयों के चलते प्रभावी ढंग से नहीं हो सका। राहत वितरण, पुनर्वास, सड़क और पुलों की मरम्मत, सब कुछ कागजी फाइलों तक सीमित रह गया और जनता अपनी पीड़ा में अकेली खड़ी रही।

इन सबके बीच राज्य का राजनीतिक नेतृत्व एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने में व्यस्त रहा। इस टकराव ने प्रशासन में ठहराव पैदा किया, जिसके चलते सरकारी मशीनरी जमी हुई दिखी। एक मजबूत और स्थिर शासन मॉडल पर आधारित हिमाचल, जिसे कभी शांतिपूर्ण, स्वच्छ और व्यवस्थित प्रशासन के लिए जाना जाता था, आज देश के उन प्रदेशों की सूची में शामिल हो रहा है जो आर्थिक और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। इन तीन वर्षों की तुलना जब पूर्ववर्ती शासन से की जाती है, तो कई नागरिक खुलकर कहने लगे हैं कि राज्य बेहतर स्थिति में था। बुनियादी ढाँचे से लेकर वित्तीय अनुशासन तक, अनेक मोर्चों पर वह एक व्यवस्थित दिशा में बढ़ रहा था। आज की स्थिति में लोग यह महसूस कर रहे हैं कि घोषणाओं और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच खाई बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 11 वर्षों से विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र का विकास-केन्द्रित दृष्टिकोण, युवा-उन्मुख कार्यक्रम और बुनियादी ढाँचे में तेज सुधार राष्ट्र को नई ऊँचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय में हिमाचल की वर्तमान अव्यवस्थित स्थिति और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है क्योंकि राष्ट्रीय प्रगति के बीच राज्य पीछे जा रहा है।

हिमाचल के लोगों ने 2022 में विश्वास के साथ कांग्रेस की गारंटियों को स्वीकार किया था। उन्हें लगा था कि राज्य विकास, रोजगार और स्थिरता की नई दिशा पाएगा। तीन वर्षों की यह यात्रा अब उन्हें ऐसी वास्तविकता दिखा रही है जहां आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी, अपराध, कर्ज और अव्यवस्था ने उम्मीदों को निचोड़ कर रख दिया है। फलस्वरूप हिमाचल आज देश के सबसे कमजोर और सबसे खराब तरीके से संचालित राज्यों की श्रेणी में गिना जा रहा है। राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होता है। यदि शासन जनता के जीवन को सरल बनाने के बजाय बोझ बढ़ाए, वादों को अधूरा छोड़े, युवाओं को बेरोजगारी में धकेले और संसाधनों का दुरुपयोग करे, तो ऐसी सरकार जनता के लिए बोझ बन जाती है। हिमाचल के नागरिक आज उसी बोझ का अनुभव कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य की वर्तमान स्थिति केवल राजनीतिक विफलताओं का दस्तावेज नहीं है, यह भविष्य के लिए चेतावनी है। ऐसे में समय आ गया है कि हिमाचल अपनी दिशा सुधारे, शासन सुधार की ओर लौटे और उन मूल्यों को पुनर्जीवित करे जिनकी वजह से यह प्रदेश हमेशा उच्च मानकों वाला माना जाता रहा है।

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के लिए नामांकन ढांचे का तीसरा चरण स्थगित किया

- यह चरण 15 दिसंबर से लागू होने वाला था, नई लागू तिथि बाद में घोषित की जाएगी

नई दिल्ली ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार के लिए नामांकन ढांचे के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। यह चरण पहले 15 दिसंबर से प्रभावी होने वाला था। सेबी ने कहा कि नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। स्थगन का कारण डिपॉजिटरी और अन्य हितधारकों को परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना बताया गया है। सेबी ने रीट और इनविट की परिभाषा में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया कि योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) अब रणनीतिक निवेशक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। इस श्रेणी में सरकारी वित्तीय संस्थान, पेंशन एवं भविष्य निधि, वैकल्पिक निवेश निधि, राज्य औद्योगिक विकास निगम, पारिवारिक ट्रस्ट और 500 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति वाले पंजीकृत मध्यस्थ शामिल हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का 10,000 करोड़ रुपये का आईपीओ शुक्रवार से खुलने वाला है। इससे पहले ही 4,815 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

इसमें प्रमुख निवेशक झुनझुनवाला परिवार, मधुसूदन केला सहित कुल 26 निवेशक शामिल हैं। कंपनी ने 22,240,841 इक्विटी शेयरों का निजी प्लेसमेंट 2,165 रुपये प्रति शेयर की दर से किया। इसमें अबुधाबी की लुनेट कैपिटल, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रीजेंट्स, आईआईएफएल एसेट मैनेजमेंट, 3पी इंडिया इक्विटी फंड (प्रशांत जैन प्रबंधित), डीएसपी इंडिया फंड, व्हाइटओक कैपिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, एचसीएल कैपिटल और प्रमुख बीमा कंपनियां जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोटक लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ और गो डिजिट शामिल हैं।

आईडीबीआई बैंक की खरीद में फेयरफैक्स आगे, कोटक महिंद्रा भी दौड़ में

नई दिल्ली ।

टोरंटो स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल आईडीबीआई बैंक के अधिग्रहण की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)से बैंक की 60.72 फीसदी नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक ऑल-कैश ऑफर देने पर विचार कर रही है। मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर इस हिस्सेदारी की कीमत करीब 7 अरब डॉलर, यानी लगभग 63 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। आईडीबीआई बैंक का वर्तमान बाजार पूंजीकरण लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपए है और वर्ष 2025 में इसके शेयर अब तक 25 फीसदी चढ़ चुके हैं। बैंक में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने की होड़ में कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल है, जो नकद और शेयरों के मिश्रित ऑफर की तैयारी कर रहा है। बोली आवेदन इस महीने के अंत तक जमा किए जा सकते हैं, हालांकि डेडलाइन बढ़ने की संभावना भी है। पहले एमिरेट्स एनबीडी ने भी रुचि दिखाई थी, लेकिन हाल ही में आरबीएल बैंक में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने के समझौते के बाद उसके दौड़ से हटने की अटकलें हैं। फेयरफैक्स, कोटक और एमिरेट्स एनबीडी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।

पहली बार चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंची , सोना भी उछला

नई दिल्ली ।

पहली बार चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती और मांग बढ़ने के बाद मल्टी कमोडिटी मार्केट (एमसीएक्सा) पर चांदी में ये उछाल आया है। चांदी 1600 रुपये उछलकर 2,00,510 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। वहीं सोने में भी रिकॉर्ड तेजी रही।

एमसीएक्स पर सोना आज करीब 2500 रुपये चढ़कर 1,34,966 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, ये इसका रिकॉर्ड ऊंचा स्तर है। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव लगभग 1,32,700 रुपए और चांदी के भाव 1,97,850 रुपए के आसपास कारोबार कर रहे थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के फरवरी कॉन्ट्रेक्ट की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ 1,32,442 रुपए पर हुई, जबकि पिछला बंद भाव 1,32,469 रुपए था। शुरुआती कमजोरी के बाद सोने में खरीदारी बढ़ी और यह कॉन्ट्रेक्ट 1,32,673 रुपए पर पहुंच गया, जो लगभग 204 रुपए की तेजी दर्शाता है। दिन के दौरान सोना 1,32,764 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंचा, जबकि 1,32,400 रुपए इसका दिन का निचला स्तर रहा। इसके विपरीत, चांदी के मार्च कॉन्ट्रेक्ट की शुरुआत सुस्त रही और पिछले बंद 1,98,942 रुपए से करीब 1,984 रुपए की गिरावट के साथ 1,96,958 रुपए पर खुला, यानी कारोबार के दौरान चांदी में दबाव बना रहा और यह 1,97,878 रुपए तक फिसल गई।

नवंबर में रूसी तेल निर्यात में अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव से भारी गिरावट

- मॉस्को का राजस्व घटकर 11 अरब डॉलर पहुंचा

नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और उनके संभावित प्रभावों के डर से नवंबर में रूसी तेल निर्यात में भारी गिरावट आई। कुल निर्यात लगभग 6.9 मिलियन बैरल प्रति दिन रह गया, जो पिछले महीने की तुलना में 420,000 बैरल प्रति दिन कम है। इस गिरावट के चलते रूस का तेल राजस्व 11 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल की तुलना में 3.6 अरब डॉलर कम है। रूस के यूराल कच्चे तेल की कीमतें 43.52 डॉलर प्रे ति बैरल तक गिर गईं, यानी 8.2 डॉलर प्रे ति बैरल की कमी। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं, जैसे भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क, जिससे खरीदारों पर दबाव और बढ़ा। आईईए के अनुसार नवंबर में वैश्विक तेल आपूर्ति में 610,000 बैरल प्रति दिन की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट में मुख्य योगदान ओपेक देशों (80 फीसदी) का रहा, जबकि अमेरिका, ब्राजील और जैव ईंधन उत्पादकों ने भी आपूर्ति कम करने में भूमिका निभाई। ईरान का उत्पादन 1.9 मिलियन बैरल प्रे ति दिन स्थिर रहा। आईईए ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में वैश्विक तेल आपूर्ति 3 मिलियन बैरल प्रे ति दिन बढ़ेगी और 2026 में यह वृद्धि 2.4 मिलियन बैरल प्रे ति दिन होगी। 2026 में वैश्विक मांग 860,000 बैरल प्रे ति दिन रहने का अनुमान है। मांग में वृद्धि का आधा हिस्सा गैसोलीन और जेट या केरोसिन से आएगा, जबकि ईंधन तेल की मांग घटती रहेगी। रूसी तेल पर यूरोपीय संघ के आगामी प्रतिबंधों और रिफाइनरी ठप होने की वजह से उत्पाद क्रैक और रिफाइनिंग मार्जिन तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 449, निफ्टी 148 अंक उछला

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को भी तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं गत दिवस भी बाजार उछाल के साथ बंद हुंआ था। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिना बाजार में ये तेजी एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीददारी हावी होने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में 449.53 अंक बढ़कर 85,267.66 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 148.40 अंक उछलकर 26,046.95 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान धातु और संपत्ति शेयरों में तेजी से बाजार उछला।

निफ्टी मेटल 2.63 फीसदी और निफ्टी रियल्टी 1.53 फीसदी ऊपर आये। निफ्टी ऑटो 0.58 फीसदी , निफ्टी आईटी 0.47 फीसदी , निफ्टी एनर्जी 0.83 फीसदी , निफ्टी इन्फ्रा 1.18 फीसदी उछले। वहीं निफ्टी एफएमसीजी 0.24 फीसदी और निफ्टी मीडिया 0.05 फीसदी नीचे आकर बंद हुए। बाजार में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों के कारण तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 705.25 अंक बढ़कर 60,283.30 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 161.90 अंक उडलकर 17,389.15 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, टाइटन और टीसीएस के शेयरों को लाभ हुआ जबकि एचयूएल, सन फार्मा, आईटीसी, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस और एसबीई के शेयर गिरे। इससे पहले आज सुबह भारतीय शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत रही। सेंसेक्स 85,051 अंकों पर मजबूती के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में इसमें तेजी जारी रही और 302.71 अंक की बढ़त के साथ 85,120.84 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी-50 भी मजबूती के साथ 25,971 अंकों पर खुला। कुछ ही समय में यह 26,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया।

नवंबर में रूसी तेल निर्यात में अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव से भारी गिरावट

मॉस्को का राजस्व घटकर 11 अरब डॉलर पहुंचा

नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और उनके संभावित प्रभावों के डर से नवंबर में रूसी तेल निर्यात में भारी गिरावट आई। कुल निर्यात लगभग 6.9 मिलियन बैरल प्रति दिन रह गया, जो पिछले महीने की तुलना में 420,000 बैरल प्रति दिन कम है। इस गिरावट के चलते रूस का तेल राजस्व 11 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल की तुलना में 3.6 अरब डॉलर कम है। रूस के यूराल कच्चे तेल की कीमतें 43.52 डॉलर प्रे ति बैरल तक गिर गईं, यानी 8.2 डॉलर प्रे ति बैरल की कमी। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं, जैसे भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क, जिससे खरीदारों पर दबाव और बढ़ा। आईईए के अनुसार नवंबर में वैश्विक तेल आपूर्ति में 610,000 बैरल प्रति दिन की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट में मुख्य योगदान ओपेक देशों (80 फीसदी) का रहा, जबकि अमेरिका, ब्राजील और जैव ईंधन उत्पादकों ने भी आपूर्ति कम करने में भूमिका निभाई। ईरान का उत्पादन 1.9 मिलियन बैरल प्रे ति दिन स्थिर रहा। आईईए ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में वैश्विक तेल आपूर्ति 3 मिलियन बैरल प्रे ति दिन बढ़ेगी और 2026 में यह वृद्धि 2.4 मिलियन बैरल प्रे ति दिन होगी। 2026 में वैश्विक मांग 860,000 बैरल प्रे ति दिन रहने का अनुमान है। मांग में वृद्धि का आधा हिस्सा गैसोलीन और जेट या केरोसिन से आएगा, जबकि ईंधन तेल की मांग घटती रहेगी। रूसी तेल पर यूरोपीय संघ के आगामी प्रतिबंधों और रिफाइनरी ठप होने की वजह से उत्पाद क्रैक और रिफाइनिंग मार्जिन तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।

इंडिगो की उड़ानें निरस्त होने से 1,800 करोड़ का नुकसान

- कुल 2,686 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है वित्तीय दबाव

नई दिल्ली ।

एयरलाइन कंपनी इंडिगो को वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण अब तक कंपनी को लगभग 1,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

शुरुआती चरण में ही 9 दिसंबर तक रिफंड के रूप में 900 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ। यदि नियामक एजेंसियां मुआवजे का आदेश देती हैं, तो यह वित्तीय बोझ और बढ़ सकता है। एविएशन मिनिस्ट्री के पैसेंजर चार्टर के अनुसार, अगर उड़ान 2 घंटे से अधिक देरी या कैंसिल होती है और यात्रियों को 24 घंटे पहले सूचित नहीं किया जाता, तो एयरलाइन को 10,000 या बेसिक किराया प्लस फ्यूल चार्ज (जो कम हो) के बराबर मुआवजा देना होगा। 1 से 9 दिसंबर के बीच 8.86 लाख पीएनआर कैंसिल होने के कारण इंडिगो पर लगभग 886 करोड़ रुपए का मुआवजा भुगतान बन सकता है।

अगर यह रिफंड के साथ दिया गया, तो कंपनी का कुल वित्तीय दबाव 2,686 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इंडिगो ने ऑपरेशनल स्थिति में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। 3 से 5 दिसंबर के बीच कैंसिल या लंबी देरी से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया गया है। यह वाउचर अगले 12 महीनों में किसी भी उड़ान की बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । रुपया शुक्रवार को दो पैसे की गिरावट के साथ ही 90.52 पर बंद हुआ। आज सुबह कारोबार में रुपया 24 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.56 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता एवं विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से भी निवेशकों की भावना प्रभावित होने से रुपया दबाव में है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि कीमती धातुओं की वैश्विक कीमतों में उछाल के बीच आयातकों द्वारा डॉलर की आक्रामक खरीद से भी रुपया पर दबाव पड़ा। अंतरबैंक विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.43 पर खुला। फिर डॉलर के मुकाबले 90.56 पर लुढ़क गया जो पिछले बंद भाव से 24 पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया गुरुवार को 38 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.32 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी की बढ़त के साथ 98.37 पर रहा।

निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 50,000 करोड़ एयूएम क्लब में किया प्रवेश

- 3 साल में 18 और 5 साल में 22 फीसदी से ज्यादा दिया रिटर्न

नई दिल्ली ।

निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। तीन साल में इसने 18.46 फीसदी और पांच साल में 22.43 फीसदी का रिटर्न दिया, जिससे यह अन्य प्रमुख लार्ज कैप फंड्स जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और इन्वेस्को इंडिया के मुकाबले आगे निकल गया।

लार्ज कैप फंड नए और जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं। इन फंड्स का पोर्टफोलियो ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करता है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिरता बनी रहती है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 50,000 करोड़ रुपये के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) क्लब में प्रवेश कर लिया है। यह उपलब्धि कम निवेश के बावजूद हासिल हुई है, क्योंकि हालिया बाजार तेजी, मुनाफावसूली और त्योहारी सीजन के दौरान तरलता की जरूरतें बढ़ी हैं। फंड का प्रदर्शन इंडेक्सिंग पर नहीं, बल्कि सक्रिय निवेश और गहन शोध पर आधारित है। फंड मैनेजर बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं, जिससे उचित मूल्य पर वृद्धि होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड निवेश की रीढ़ हैं।

लंबी अवधि में ये स्थिर और निरंतर रिटर्न देने के साथ संभावित लाभांश भी प्रदान करते हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करता है।

इंडिगो सीसीआई की जांच के घेरे में

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आंतरिक रूप से यह देख रहा है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है और जांच स्वतः संज्ञान के आधार पर की जा रही है। इंडिगो घरेलू बाजार में 65 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखती है। जांच में कंपनी के प्रभुत्व, विशेष मार्गों पर नियंत्रण और इसका दुरुपयोग-शोषणकारी या बहिष्करणकारी- जांचने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रभुत्व में होना अपने आप में अपराध नहीं है, केवल इसका दुरुपयोग ही नियमों का उल्लंघन माना जाता है। 2 दिसंबर से इंडिगो ने सैकड़ों उड़ानें रद्द कीं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए। नए उड़ान 'ड्यूटी' नियमों को लागू करने में योजना की कमी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। डीजीसीए भी एयरलाइन के संचालन की निगरानी बढ़ा रहा है। सीसीआई का उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके अधिकारों में जांच, जुर्माना और निषेधाज्ञा जारी करना शामिल है।

मेटा इंडिया में अमन जैन बने सार्वजनिक नीति प्रमुख

नई दिल्ली । मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। जैन अगले साल की शुरुआत में कंपनी में शामिल होंगे और एपीएसी के नीति उपाध्यक्ष साइमन मिलनर के अधीन काम करेंगे। उनके पास अमेज़न, गूगल, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में 20 वर्षों का अनुभव है। मेटा का उद्देश्य भारत में समावेशी, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार इंटरनेट बनाना है। जैन की नियुक्ति से कंपनी को नीति निर्माण और उद्योग हितधारकों के साथ बेहतर साझेदारी में मदद मिलेगी।

एनपीएस को सोने-चांदी ईटीएफ में निवेश की अनुमति

- लगभग 1.7 बिलियन डॉलर निवेश के अवसर मिलेंगे

नई दिल्ली । नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अब अपने फंड का एक फीसदी सोने और चांदी के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश कर सकता है। यह पहली बार है जब भारतीय नियामक ने पेंशन फंडों को कीमती धातुओं में निवेश की अनुमति दी। इस पहल से लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के निवेश के अवसर खुलते हैं। सोने और चांदी ने इस साल क्रमशः 61 फीसदी और 114 फीसदी की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। ईटीएफ के जरिए निवेशकों को धातुओं में सीधी हिस्सेदारी लेने का आधुनिक तरीका मिल गया है। एक शोध` विशेषज्ञ के मुतो बिक यह कदम सोने को एक प्रभावी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ायर के रूप में स्थापित करता है। एनपीएस पिछले दो दशकों से संचालित है और 177 बिलियन डॉन्लर के टैक्स-इफिशिएंट रिटायरमेंट फंड्स का प्रबंधन करता है। भारत दुनिया के शीर्ष सोने उपभोक्ताओं में है। ईटीएफ ने सोने और चांदी में निवेश को आधुनिक और सुरक्षित विकल्प बना दिया है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री नवंबर में 19 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली । सोसायटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने बताया कि नवंबर 2025 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 18.7 फीसदी बढ़कर 4,12,405 इकाइयों तक पहुंच गई। इसी तरह, दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 21 फीसदी की वृद्धि के साथ 19,44,475 इकाइयों तक पहुंची। सियाम ने कहा कि त्योहारों के बाद भी मजबूत मांग ने इस वृद्धि में योगदान दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उपभोक्ता विश्वास और वाहन बाजार की स्थिर रिकवरी का संकेत है।

एसआईपी के जरिए छोटी बचत से बड़े सपने पूरे करें

- 5,000 की एसआईपी करके 18 महीनों में बन जाएं लखपति

नई दिल्ली । आज के दौर में म्यूचुअल फंड में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) ने निवेशकों के लिए रास्ता आसान बना दिया है। एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप केवल 5,000 रुपए जैसी छोटी राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और लंबी अवधि में अच्छा-खासा फंड तैयार कर सकते हैं। जो लोग निवेश की शुरुआत करते हैं, उनका पहला लक्ष्य अक्सर लखपति बनना होता है। पारंपरिक निवेश के तरीकों की तुलना में एसआईपी में रिटर्न ज्यादा होने के कारण यह लक्ष्य जल्दी हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने 5,000 निवेश करते हैं और अनुमानित सालाना रिटर्न 12 फीसदी रहता है, तो 18 महीनों में आपका कुल फंड लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड का वास्तविक रिटर्न बाजार की चाल पर निर्भर करता है। इक्विटी फंड में रिटर्न अधिक होता है, लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। कम जोखिम वाले फंड में रिटर्न थोड़ी कम होती है, इसलिए लक्ष्य समय के हिसाब से मासिक निवेश बढ़ाना पड़ सकता है। एसआईपी का असली फायदा तब दिखता है जब निवेशक धैर्य रखते हैं और लंबी अवधि तक निवेश जारी रखते हैं। नियमित मासिक निवेश और सही फंड चयन से छोटी बचत भी बड़ा फंड बना सकती है।

दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया उर्वशी रौतेला के डांस मूव्स ने

बॉलीवुड की प्रतिभाशाली एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के दमदार सेल्फ डांस चैलेंज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक्ट्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उनके एनर्जेटिक मूव्स, तकनीकी डांस स्किल्स और बेहतरीन स्टेज प्रेज़ेंस ने दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया और फैंस लगातार इसे शेयर और रीक्रिएट कर रहे हैं। वीडियो में उर्वशी का आत्मविश्वास, ग्रेस और कच्चा टैलेंट साफ झलकता है। उनकी हर मूवमेंट में एक अलग ही चमक दिखाई देती है, जिसने लोगों को उनकी तुलना बेयॉस और जेनिफर लोपेज जैसी ग्लोबल सुपरस्टार्स से करने पर मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स की बाढ़ ला रहे हैं और उन्हें 'इंडिया की डांस क्वीन' तक कह रहे हैं। कई फैंस ने उनके सिग्नेचर स्टेप्स को कॉपी कर अपने संस्करण भी बनाए हैं, जिससे यह चैलेंज और ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। इस चैलेंज की खासियत यह है कि यह उर्वशी की एक अलग ही झलक पेश करता है—फिल्मों और स्टेज शो से अलग, ज्यादा व्यक्तिगत और जुड़ाव भरा अंदाज। उनका यह सेल्फ-डांस चैलेंज दर्शाता है कि वह सिर्फ कैमरे पर ही नहीं, बल्कि अपने वास्तविक अंदाज में भी कितनी सहज और प्रतिभाशाली हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि उनके टैलेंट, कॉन्फिडेंस और स्टारडम का उत्सव है। फैंस की प्रतिक्रियाएं भी बेहद उत्साहजनक रही हैं। किसी ने लिखा, 'उर्वशी इज़ गोल्स! उनकी एनर्जी का कोई जवाब नहीं', तो वहीं एक अन्य ने कहा, 'इसीलिए वो इंडिया की बेयॉस हैं।' इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि उर्वशी ने अपनी कला से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। इस वायरल चैलेंज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उर्वशी रौतेला सिर्फ सुंदरता और ग्लैमर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अथक मेहनत और बहुमुखी प्रतिभा के चलते इंडस्ट्री की शीर्ष परफॉर्मर्स में शामिल हैं। उनके इस वीडियो ने न केवल यादगार पल बनाए हैं बल्कि कई युवा कलाकारों को भी प्रेरित किया है। उर्वशी रौतेला लगातार यह साबित कर रही हैं कि वह हर बार कुछ नया और ऊर्जावान लेकर आती हैं—और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है।

मात्र 10 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था रति अग्निहोत्री ने

बॉलीवुड एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री को एक समय खूबसूरती और संजीदा अभिनय की मिसाल माना जाता था। दर्शक उन्हें 'स्वर्ग से उतरी अप्सरा' तक कहकर पुकारते थे। रति अग्निहोत्री भी बॉलीवुड के कई प्रतिभाशाली कलाकारों में शामिल हैं। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय और मॉडलिंग का शौक था और मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए, 16 साल की उम्र में उन्हें तमिल फिल्म 'पुदिया वरपुकल' में काम करने का अवसर मिला। यह उनकी पहली तमिल फिल्म थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उन्हें साउथ इंडस्ट्री में पहचान दिला गई। इसके बाद वह कमल हासन, रजनीकांत और चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नजर आईं। हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'एक दूजे के लिए' से हुई, जिसमें उन्होंने कमल हासन के साथ काम किया। फिल्म बड़ी हिट रही और रति को रातों-रात स्टारडम मिल गया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला, जिससे बॉलीवुड में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। 1980 के दशक में उन्होंने 'कुली', 'तवायफ', 'अय्याश', 'शौकीन', 'मुझे इंसाफ चाहिए', 'मैं आवारा हूं' और 'फर्ज और कानून' जैसी कई सफल फिल्मों में मजबूत भूमिकाएँ निभाईं। करियर के शिखर पर रहते हुए रति ने 1985 में आर्किटेक्ट अनिल विरवानी से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि उन्हें आगे भी कई बड़े ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने परिवार पर ध्यान देने के लिए केवल चुनिंदा साइड रोल स्वीकार किए। 2001 में उन्होंने 'कुछ खट्टी कुछ मीठी' के साथ फिल्मों में वापसी की। इसके बाद 'क्यों हो गया नाज', 'हम तुम', 'ये है जलवा', 'देव' और 'पहचान' जैसी फिल्मों में साइड रोल करके भी उन्होंने अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराया।

धर्मेंद्र के जन्मदिन पर सुभाष घई ने लिख दिल छू लेने वाला संदेश

बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई ने अभिनेता धर्मेंद्र की 90वीं जन्म जयंती पर उन्हें खास अंदाज में याद किया। सोशल मीडिया पर उनके साथ जुड़ी पुरानी यादों को साझा करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी। घई ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की एक स्केच तस्वीर पोस्ट करते हुए एक दिल छू लेने वाला संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने अभिनेता की शानदार फिल्मी यात्रा, उनके व्यक्तित्व और बहुमुखी अभिनय क्षमता की जमकर सराहना की। सुभाष घई ने अपने संदेश में लिखा, ‘60 साल से हमारे हीमैन स्क्रीन स्टार धर्मेंद्र को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े निर्देशक के साथ काम किया है। सीधा-साधा नौजवान, एंग्री एक्शन हीरो, संवेदनशील प्रेमी, कवि, कमीडियन, ऐतिहासिक किरदार या फिर अध्यात्म से जुड़ा चरित्र हर रूप में दर्शकों ने उन्हें सराहा। यह सब उनके सादगी भरे साफ दिल और मेहनत की वजह से संभव हो पाया।' घई ने आगे लिखा कि उनकी नजर में धर्मेंद्र एक ऐसे सितारे थे, जिन्होंने अपने अभिनय के जरिए ना सिर्फ शुभचिंतकों का दिल जीता, बल्कि इंसानियत और सरलता की मिसाल भी कायम की। घई ने अपने संदेश में विशेष रूप से वर्ष 1981 में रिलीज हुई अपनी फिल्म 'क्रोधी' का उल्लेख किया। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने मुख्य किरदार निभाया था, जो एक पढ़ा-लिखा माफिया डॉन होता है और बाद में जीवन की घटनाओं से प्रभावित होकर अध्यात्म का मार्ग अपनाता है।

घई ने इसे अपने करियर की भी खास फिल्म बताया और कहा, 'उन्होंने मेरी फिल्म 'क्रोधी' में जो चुनौतीपूर्ण रोल किया, वह आज भी मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में शामिल है। इस किरदार में गुस्से, बदले और आध्यात्मिक बदलाव का अनोखा संगम था, जिसे धर्मेंद्र ने बेहद खूबसूरती से निभाया। हैप्पी बर्थडे पाजी, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।' 'क्रोधी' एक दमदार एक्शन थ्रिलर थी, जिसमें धर्मेंद्र के साथ शशि कपूर, जीनत अमान, प्रेमनाथ, रंजीता, सचिन, प्राण और अमरीश पुरी जैसे कई नामी कलाकार नजर आए। फिल्म में विशेष भूमिकाओं में हेमा मालिनी और मौसमी चटर्जी भी शामिल थीं। दर्शकों ने फिल्म में धर्मेंद्र के द्वारा गुस्से और प्रतिशोध से भरे व्यक्ति से शांत और आध्यात्मिक व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन को खूब सराहा था।

गुमनामी की जिंदगी जी रही एक्ट्रेस प्रिया गिल

अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री प्रिया गिल आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 1999 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'सिर्फ तुम' में अभिनय के बाद अभिनेत्री प्रिया गिल अचानक रातोंरात स्टार बन गई थीं, लेकिन समय के साथ वह फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गईं। एक्ट्रेस आज पूरी तरह गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली प्रिया गिल ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों शाहरुख खान और सलमान खान के साथ भी काम किया, लेकिन मायूसी और संघर्ष ने उन्हें कैमरे की चमक से बहुत दूर कर दिया। प्रिया गिल ने 1995 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट बनकर मनोरंजन जगत में कदम रखा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के साथ 1996 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरे मेरे सपने' से की। फिल्म में उनकी एक्टिंग की सराहना हुई, लेकिन उन्हें उस फिल्म की तलाश थी जो उनके करियर को नई ऊंचाई दे। यह मौका उन्हें मिला 1999 में आई फिल्म 'सिर्फ तुम' से, जिसमें उन्होंने संजय कपूर के साथ काम किया। फिल्म रिलीज होते ही प्रिया गिल की मीठी मुस्कान, नैचुरल एक्टिंग और सादगी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह रातोंरात स्टार बन गईं। सफलता के इस दौर में प्रिया गिल ने बड़े सितारों के साथ भी बेहतरीन भूमिकाएँ निभाईं। वह 2000 में आई फिल्म 'जोश' में शाहरुख खान के साथ मुख्य भूमिका में नजर आईं। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी थीं, जो शाहरुख की बहन बनी थीं, लेकिन प्रिया गिल ने बतौर हीरोइन अपनी अलग पहचान छोड़ी। इसके अलावा उन्होंने सलमान खान के साथ 'बड़े दिलवाला' और नागार्जुन जैसे साउथ के सुपरस्टार के साथ फिल्में कीं। हालांकि, 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'बड़े दिलवाला' उनके करियर के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुई। फिल्म असफल रही और इसके बाद उन्हें फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं मिलना बंद हो गया।

अभिनेत्री दीया मिर्जा का प्रेरणादायक है सफर

महज 20 साल की उम्र में बतौर मॉडल करियर की शुरुआत करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा आज फिल्म इंडस्ट्री की सफल और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। हाल ही में दीया मिर्जा अपना जन्मदिन मनाया। उनका सफर सिर्फ ग्लैमर की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों से भी गहराई से जुड़ा है। दीया को उनकी पहली पहचान 2001 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' की 'रीना मल्होत्रा' के किरदार से मिली, जिसने दर्शकों के दिलों में उन्हें हमेशा के लिए बसा दिया। दीया मिर्जा का जन्म 9 दिसंबर 1981 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता फ्रैंक हैंडरिच जर्मन ग्राफिक और आर्किटेक्चर डिजाइनर थे, जबकि मां दीपा मिर्जा बंगाली इंटीरियर डिजाइनर और लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं। जब दीया सिर्फ साढ़े चार साल की थीं, तभी उनके माता-पिता अलग हो गए। बचपन की चुनौतियों के बावजूद दीया ने पढ़ाई और करियर दोनों में सफलता हासिल की। उन्होंने अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की और कॉलेज के दौरान ही एक मीडिया फर्म में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी शुरू कर दी। इसी दौरान वह प्रिंट और टीवी विज्ञापनों में मॉडलिंग करने लगीं और कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनीं। साल 2000 में दीया ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और रनर-अप रहीं। इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया और सिर्फ 18 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में उनकी सादगी, आत्मविश्वास और गरिमा की खूब चर्चा हुई। इसी के बाद बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुले और 2001 में आई फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' ने उन्हें स्टारडम दिलाया। फिल्म में आर। माधवन और सैफ अली खान के साथ दीया की केमिस्ट्री और उनकी मासूमियत को दर्शकों ने भरपूर पसंद किया। फिल्मी करियर में दीया ने 'संजू', 'थप्पड़', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'एसिड फैक्ट्री', और 'सलाम मुंबई' जैसी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। मगर वह कभी सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहीं। दीया पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार सक्रिय रही हैं। वह संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एंबेसडर हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अभियानों का नेतृत्व करती रही हैं। साल 2019 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'वन इंडिया स्टोरी' की शुरुआत की, जिसके जरिए वह समाज से जुड़े सार्थक कंटेंट बनाने का काम कर रही हैं।

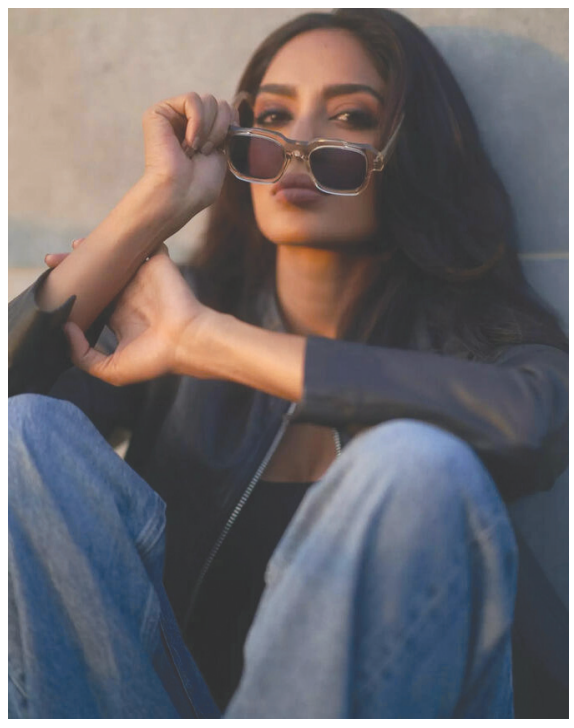

जींस और ब्लैक जैकेट पहनकर शोभिता धुलिपाला ने दिखाया स्वैग

आमतौर पर साड़ी और लहंगे में नजर आने वाली साउथ की मशहूर एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में जींस और ब्लैक जैकेट पहनकर ऐसा स्वैग दिखाया कि फैंस उनकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा तक से करने लगे। उनका यह मॉडर्न अवतार देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग उनके नए स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। नागार्जुन की बहू बनने के बाद से शोभिता का हर लुक लाइमलाइट में रहता है, लेकिन इस बार उनका बदला हुआ स्टाइल सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट, हाई-वेस्ट डेनिम जींस और अंदर ब्लैक टैंक टॉप पहनकर एकदम ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक क्रिएट किया। आउटफिट बेहद सिंपल था, लेकिन इसे जिस अंदाज में उन्होंने कैरी किया, वह उनके पूरे व्यक्तित्व को अलग ही स्तर पर ले गया। उनका पोज़, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज हर फोटो में कूल और स्टाइलिश वाइब दे रहे थे। ब्लैक लेदर जैकेट इस पूरे लुक का सबसे आकर्षक हिस्सा बन गया। इसकी फिटिंग, सिल्वर ज़िप्स और स्टाइलिश कट्स ने उनके बोल्ड अंदाज को और निखारा। वहीं, ब्लैक टैंक टॉप ने उनके लुक में परफेक्ट बोल्डनेस जोड़ दी। प्लेन होने के बावजूद इसका फिट और स्टाइल आउटफिट को खास बना रहा था। हाई-वेस्ट जींस का चुनाव भी बेहतरीन रहा, जिसने उनके मॉडर्न और कंफर्टेबल स्टाइल को पूरा किया। गोल सिल्वर बटन और डीप पॉकेट्स ने जींस को और आकर्षक बनाया, जबकि पॉकेट में हाथ डालकर दिए गए उनके पोज़ तस्वीरों को और भी क्लासी बना रहे थे। शोभिता ने इस पूरे लुक को एक्सेसरीज के साथ ओवरडन नहीं किया। उन्होंने केवल एक चंकी सिल्वर नेकलेस पहना और बाकी ज्वेलरी को पूरी तरह इग्नोर किया। उनकी आंखों पर लगा ब्लैक सनग्लास उनके कूल अंदाज का सबसे बड़ा हाइलाइट बना। साधारण वेस्टर्न आउटफिट को उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ पेश किया, उसने उन्हें और भी गॉर्जियस बना दिया। फैंस उनके इस अवतार पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने उन्हें 'साउथ की प्रियंका चोपड़ा' कहा तो किसी ने 'लेडी सिंघम'। कई लोगों का कहना है कि शोभिता बिना किसी विशेष मेहनत के ही स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखने की क्षमता रखती हैं। उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस मॉडर्न, bold और कॉन्फिडेंट लुक पर फिदा हो गए हैं। बता दें कि साउथ स्टार नागार्जुन की बड़ी बहू और एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला अक्सर अपने एथनिक और एलीगेंट लुक्स के लिए मशहूर रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा वेस्टर्न अंदाज अपनाया कि सोशल मीडिया पर हलचल मच गई।

काम पर लौटीं कियारा आडवाणी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी मां बनने की खुशी के बाद अब दोबारा काम पर लौट आई हैं। कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 15 जुलाई को अपनी बेटी सारायाह का स्वागत किया था। माता-पिता बनने के बाद यह पहली बार है जब कियारा मीडिया कैमरों के सामने दिखाई दीं। लगभग पांच महीनों के बाद काम पर वापसी करते हुए कियारा को मुंबई में स्पॉट किया गया, जहां उन्हें देखकर फैंस बेहद उत्साहित हो गए। मदरहुड के बाद कियारा की यह पहली झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। फैंस लंबे समय से उनकी स्क्रीन पर वापसी का इंतजार कर रहे थे। मां बनने के बाद कियारा ने काफी समय परिवार को दिया और अब दोबारा अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाने की शुरुआत की है। कियारा पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड की टॉप लीग की अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी हैं और उनकी फिल्मों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि ब्रांड्स और फिल्ममेकर्स भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह किस प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए सेट पर लौटी हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह जल्द ही किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकती हैं।

डिजिटल स्पेस बदला है, खत्म नहीं हुआ: प्राजक्ता कोली

मशहूर यूट्यूबर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली कहा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का दौर न तो खत्म हुआ है और न ही धीमा पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में यह पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, तेज और अनिश्चित हो गया है।

एक्ट्रेस प्राजक्ता ने बताया कि डिजिटल स्पेस बदला है, खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दस-ग्यारह साल पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी तब केवल लॉन्ग-फॉर्म वीडियो ही चलते थे, लेकिन आज दर्शकों का ध्यान कई प्लेटफॉर्म्स में बंट चुका है। नए-नए फॉर्मेट्स और ट्रेंड्स लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे क्रिएटर्स को भी खुद को लगातार अपडेट रखना पड़ता है। उन्होंने 2017 के डिजिटल बूम को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि इसी बूम की वजह से आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकॉनमी बन चुका है, जहां हर बड़ा ब्रांड भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहता है। अपनी जर्नी को वह पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल बताती हैं। उनके मुताबिक डिजिटल इंडस्ट्री में कोई तय रोडमैप, पैटर्न या रिदम नहीं होता। कभी कुछ वीडियो अच्छा चल जाते हैं और लगता है कि सब सेट हो गया, लेकिन अगला वीडियो आते-आते हालात पूरी तरह बदल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस फील्ड का यही रोमांच है—यह एक रोलरकोस्टर राइड की तरह है जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौती और नया मौका होता है। बीते दस साल में उनकी सबसे बड़ी सीख यही रही है कि बदलाव को पहचानना और तुरंत अपनाना जरूरी है। प्राजक्ता ने कहा कि उनके लिए हमेशा यह समझना महत्वपूर्ण रहा कि किस समय क्या चल रहा है, क्या अब काम नहीं कर रहा और फिर बिना रुके नई दिशा की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उनकी मान्यता है कि यही एप्रोच उन्हें इंडस्ट्री में लगातार प्रासंगिक बनाए रखती है। डिजिटल स्पेस को वह चुनौतीपूर्ण के साथ-साथ बेहद रोमांचक भी मानती हैं।

अंडर 19 एशिया कप में रविवार को होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला

वैभव पर रहेंगी नजरें, हाथ नहीं मिलने को लेकर जारी गतिरोध टूटेगा !

दुबई (एजेंसी)। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में रविवार को होने वाली भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर प्रशंसकों में उत्साह चरम पर है। इस मैच में सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी। वैभव ने जिस प्रकार यूएई के खिलाफ मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी की है। उससे तय है कि वह पाक के खिलाफ भी उसी अंदाज में उतरेंगे। विश्वकप में ये देखना होगा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं या नहीं।

माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) टीम का इस मैच में हाथ मिलाने से नहीं रोकेगी। इसका कारण है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा है कि अंडर-19 स्तर पर खेलभावना को मजबूत करने पर उसका ध्यान रहेगा।

वहीं आईसीसी ने कहा है कि अगर भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते, तो इसकी जानकारी पहले से मैच रेफरी को देनी होगी। आईसीसी का प्रयास है कि जूनियर क्रिकेट में सही संदेश जाए और किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें, ग्रुप एक से सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं क्योंकि अन्य टीमें मलेशिया और काफी कमजोर हैं। भारतीय टीम के लिए राहत की बात ये है कि वैभव सूर्यवंशी अच्छी फॉर्म में हैं। वहीं कप्तान आयुष म्हात्रे ने हाल में घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था। म्हात्रे ने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया था। वहीं वैभव ने सबसे कम उम्र में शतक लगाया था। इस प्रकार के इनके प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है।

अंडर-19 एशिया कप की टीमें

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, यूएई

ग्रुप बीः बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल

भारतीय टीमः आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस के अधीन), उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज.

स्टैंडबाय खिलाड़ीः राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत।

मुश्ताक अली ट्रॉफी : नीतीश की हैट्रिक बेकार गयी, मध्य प्रदेश ने आंध्र को हराया

पुणे (एजेंसी)। मध्य प्रदेश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग स्टेज के अपने पहले मैच में आंध्र प्रदेश को चार विकेट से हरा दिया। इस मैच में आंध्र के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने हैट्रिक लगायी पर इसके बाद भी वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाये। मध्य प्रदेश ने इस मैच में खराब शुरुआत से उबरकर 113 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। रेड्डी ने तीसरे ओवर में हर्ष गवली, हरप्रीत भाटिया और रजत पाटीदार के विकेट लिए।

वेंकटेश अय्यर के आउट होने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश का स्कोर चार विकेट पर 37 रन हो गया। ऐसे में आंध्र की जीत की उम्मीदें बनीं पर ऋषभ चौहान और राहुल बाथम ने पांचवें विकेट के लिए 73 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को संभाल लिया। चौहान ने 43 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 47 रन बनाए जबकि बाथम 32 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे मध्य प्रदेश ने 15 गेंद बाकी रहते जीत हासिल करने के साथ ही चार जरूरी अंक प्राप्त किये।

वहीं इससे पहले रेड्डी ने विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन बनाये। भरत ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए जिससे आंध्र की टीम 19.1 ओवर में 112 रन तक पहुंची। मध्य प्रदेश की ओर से शिवम शुक्ला ने 4 जबकि त्रिपुरेश सिंह ने 3 विकेट लिए। वहीं बाथम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।

सूर्यकुमार ने हार की जिम्मेदारी ली, अक्षर को पहले भेजे जाने के फैसला का भी बचाव किया

मुल्लांपुर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में हार पर निराशा जताते हुए इसकी जिम्मेदारी ली है। सूर्यकुमार ने कहा कि उन्हें इस मैच में जिम्मेदारी लेनी थी पर वह उसमें सफल नहीं हो पाये। इस मैच में भारतीय टीम 214 रनों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पायी थी। इस मैच में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजने के फैसले का भी सूर्या ने बचाव करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में उसने शुरुआत में उतारने पर बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है जिसको देखते हुए उसे इस बार अवसर दिया गया। अक्षर को पहले भेजने के कारण मुख्य कोच गौतम गंभीर के फैसलों पर भी सवाल उठे थे। सूर्यकुमार ने कहा कि अक्षर ने एकदिवसीय और टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी की है हालांकि वह इस मैच में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाये। कप्तान ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए आगामी मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की बात कही।

सूर्यकुमार ने कहा, हमने पहले गेंदबाजी करके भी गलती की जबकि हमें बल्लेबाजी करनी चाहिये थी पर कहा कि टीम को इससे सीखने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि हमें दूसरी योजना भी लेकर चलनी चाहिये थी पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने दूसरी पारी में विरोधी टीम की गेंदबाजी देखकर सबक लिया है। अब हम अगले मैच में उसी के अनुसार गेंदबाजी करना चाहेंगे।

सूर्यकुमार ने कहा, हम हर मैच में अभिषेक शर्मा पर आधारित नहीं रह सकते। मुझे और शुभमन गिल को अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिये थी पर हम ऐसा नहीं कर पाये। शुभमन पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद मुझे लंबी पारी खेलते हुए मैच आगे ले जाना चाहिये था पर मैं ऐसा नहीं कर पाया।

डिकॉक का अर्धशतक, भारत को 51 रन से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 1-1 से बराबर की

मुल्लांपुर (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका ने विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (90 रन) की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर बृहस्पतिवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत को 51 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। अब तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा।

पहले मैच में महज 74 रन पर आउट होने वाली दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट पर 213 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया जिसमें डिकॉक की 46 गेंद की पारी में सात छक्के और पांच चौके जड़े थे। डिकॉक ने कप्तान एडन मारक्रम (29 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंद में 83 रन की भागीदारी निभाई।

डोनोवन फरेरा ने नाबाद 30 रन और डेविड मिलर ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया। भारत ने पारी में 16 वाइड गेंद डाली और 22 अंतिरिक्त रन दिए जबकि दक्षिण अफ्रीका ने केवल पांच अतिरिक्त रन दिए। इस तरह भारत ने अंतिम 10 ओवर में 123 रन लुटाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरूआत काफी खराब रही जिससे टीम उबर नहीं सकी और तिलक वर्मा (62 रन) के अर्धशतक के बावजूद 19.1 ओवर में 162 रन पर आउट हो गई।

विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने 27 रन, अक्षर पटेल ने 21 रन और हार्दिक पंड्या ने 20 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए आटेनील बार्टमैन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट झटके जबकि लुंगी एनगिडी, मार्को यानसन और लुथे सिपमाला को दो दो विकेट मिले।

भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया जो खाता भी नहीं खोल सके। इस तरह खेल के इस प्रारूप में उनकी फॉर्म पर चिंता बरकरार है। एनगिडी की गेंद को डिफेंड करने की कोशिश में वह पहली स्लिप में खड़े हेंड्रिक्स को कैच दे बैठे।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दो छक्के से आठ गेंद में 17 रन बनाकर तेज शुरूआत की लेकिन यानसन की गेंद पर आउट हो गए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर डिकॉक के हाथों में समा गई।

चौथे ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव के आउट होने से स्कोर तीन विकेट पर 32 रन हो गया। दिलचस्प है कि यानसन की गेंद सूर्यकुमार के बल्ले को छूकर विकेटकीपर के हाथों में गई लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। मारक्रम ने क्षेत्ररक्षकों से पूछने के बाद रिव्यू लेने का फैसला जबकि दो सेकेंड ही बचे थे। और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और निराश सूर्यकुमार के पवेलियन लौटते हुए मैदान पर खामोशी छा गई। तिलक वर्मा ने पांचवें ओवर में सिपमाला पर एक चौका और एक छक्का जमाया। इससे पावरप्ले में भारत का स्कोर तीन विकेट पर 51 रन था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारे गए अक्षर पटेल (21 गेंद में 21 रन) ने जैसे ही तेज खेलना शुरू किया, वह बार्टमैन की गेंद पर हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक और पंड्या ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 41 गेंद में 51 रन जोड़े लेकिन तब तक जरूरी रन रेट काफी बढ़ चुका था।

राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कायक्रम में हुआ बदलाव , 31 दिसंबर की जगह 4 जनवरी से शुरु होंगे मुकाबले

नई दिल्ली । ग्रेटर नोएडा इस माह के अंत में शुरु होने वाले एलीट पुरुष और महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों को देखते हुए अब ये चैम्पियनशिप 31 दिसंबर की जगह पर 4 जनवरी से शुरु होगी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने कहा, ''सरकार द्वारा अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों के 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी होने के कारण अब ये चैंपियनशिप पर चार से 10 जनवरी 2026 तक खेली जाएगी।'' इससे पहले दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किए कि एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली प्रशासन क्षेत्र में उच्च स्तर के वायु प्रदूषण को देखते हुए ऐसे आयोजनों को टालने के लिए तत्काल कदम उठाएं। राष्ट्रीय महासंघों और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और खेल संघों से भी इस आदेश का पालन करने को कहा गया था। माना जा रहा है कि उसी को देखते हुए मुक्केबाजी चैम्पियनशिप आगे बढ़ायी गयी है।

लॉस एंजिल्स ओलंपिक में स्वर्ण जीतना है पहलवान रवि दहिया का लक्ष्य

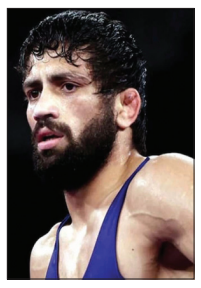

नई दिल्ली । ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि कुमार दहिया ने कहा है कि उनका लक्ष्य लॉस एंजिल्स ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है और इसके लिए वह तैयारी भी कर रहे हैं। टोक्यों ओलंपिक के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक विजेता रवि इसके बाद साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में वह जगह नहीं बना पाये और इसी कारण अब वह अपना भार वर्ग बदलकर लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। रवि 57 किग्रा की जगह अब 65 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा ले सकते हैं। उनसे देश को अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। इस खिलाड़ी का कहना है कि वह रजत तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। उनका लक्ष्य स्वर्ण जीतना है। रवि को पहचान 2018 में अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में मिली। तब 57 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता था। वहीं साल 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की थी। रवि एशियाई चैंपियनशिप में भी विजेता हैं। 2018, 2020, और 2021 में उन्होंने इसमे स्वर्ण पदक जीते थे।टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने साल 2022 में राष्ट्रमण्डल खेलों में भी दहिया ने स्वर्ण पदक जीता था।उनके पिता राकेश दहिया तो किसान हैं, लेकिन उनके चाचा मुकेश दहिया कुश्ती से जुड़े रहे हैं। इस वजह से रवि को कुश्ती विरासत में मिली है, जिसे उन्होंने अपने प्रयासों से सफल बनाया है। रवि ने केवल 10 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती प्रशिक्षण के लिए दाखिला लिया।

विनेश ने संन्यास का फैसला वापस लिया, लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलना है लक्ष्य

चंडीगढ़ (एजेंसी)। ओलंपियन महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अचानक ही संन्यास से वापसी की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया है। विनेश ने पेरिस ओलंपिक फाइनल के ठीक पहले अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित किये जाने के बाद हताशा में खेल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब विनेश ने अपने संन्यास के फैसले को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि वह 2028 लॉस एंजिस ओलंपिक में उतरना चाहती है। इसी साल अगस्त में विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेकर राजनीति में प्रवेश किया था। वहीं अब वह एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। संन्यास से वापसी की जानकारी विनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये दी है।

विनेश ने अपनी एक भावुक पोस्ट में लिखा, 'लोग आम तौर पर मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या पेरिस मेरा आखिरी सफर था? मेरे पास लंबे समय से इस सवाल का जवाब नहीं था। इस दौरान कई साल के बाद मैंने चैन की सांस ली। अपने कार्यभार को समझने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया। जीवन का उतार-चढ़ाव, देखा। मुझे अब भी खेल पसंद है। अब भी मैं प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं।' विनेश ने पोस्ट में आगे लिखा, 'शांत माहौल में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी 'आग कभी नहीं बुझती है।' ये केवल थकावट और शोर के नीचे दबी हुई थी। अनुशासन, दिनचर्या, लड़ाई ये मेरे सिस्टम में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी दूर चली गई, मेरा एक हिस्सा मैट पर ही रहा है। तो मैं यहां हूं, एक ऐसे दिल के साथ जो निडर है और एक ऐसी भावना के साथ जो झुकने से इंकार करता है, अब ओलंपिक की ओर वापस कदम रख रही हूं। और इस बार, मैं अकेली नहीं हूं। मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, 2028 ओलंपिक की इस राह पर मेरा छोटा चीयरलीडर होगा।'

तीन बार की ओलंपियन रही विनेश ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में फाइनल से ठीक एक रात पहले विनेश को अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब विनेश ने इसे अपने खिलाफ बड़ी साजिश बताया था। इसके बाद प्रशंसकों और करीब लोगों के समझाने के बाद भी विनेश नहीं मानी और संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसके बाद विनेश ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था और जुलाना सीट से 6,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।

महिला पहलवान विनेश फोगट ने संन्यास से की वापसी, तीन बार की ओलंपियन ने किया भावुक पोस्ट

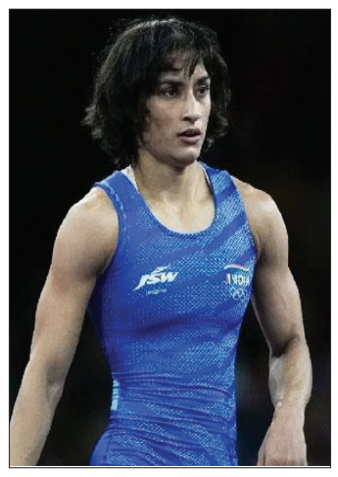

नई दिल्ली। तीन बार की ओलंपियन महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कुश्ती से संन्यास लेने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। फोगाट ने भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने संन्यास से वापसी की घोषणा करते हुए कहा कि अब उनका लक्ष्य लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना है। पिछले साल विनेश फोगाट ने पेरिस 2024 ओलंपिक के तुरंत बाद संन्यास ले लिया था। ठीक एक दिन बाद जब उन्हें स्वर्ण पदक मुकाबले से ज्यादा वजन होने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या पेरिस मेरे करियर का अंत है। लंबे समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी दूर हटने की जरूरत थी। इतने सालों में पहली बार मैंने खुद को चैन की सांस लेने दी।' उन्होंने कहा, 'मैंने अपने सफर के महत्व को समझने के लिए समय लिया, ऊंचाइयों, दिल टूटने के पलों, बलिदानों और मेरे उन रूपों को समझा जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। और इसी आत्मचिंतन में मुझे सच्चाई मिली, कि मुझे अब भी इस खेल से प्यार है। मैं अब भी प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं।'

अंडर-19 एशिया कप में वैभव ने यूएई के खिलाफ लगाया तूफानी शतक

दुबई । यहां यूएई के खिलाफ हुए अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में ही अर्धशतक लगा दिया। वैभव ने इस मैच में शतकीय पारी खेलते हुए यूएई के गेंदबाजों को कोई अवसर नहीं दिया। वैभव ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान आयुश महात्रे शुरुआत में ही आउट हो गये। आयुश तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर ही केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गये। इसके बाद वैभव ने पारी संभाली और जमकर चौके, छक्के लगाये।वैभव ने अपने पचास रन छक्के के साथ बनाये। इसके बाद पारी के 16वें ओवर में वैभव ने लगातार तीन छक्के लगा दिए। इस ओवर ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। इसके बाद। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने एक रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। वैभव ने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। वैभव ने 84 गेंदों पर 150 रन पूरे किए। आखिरकार वह 95 गेंदों में 171 रन बनाकर लौटे वैभव की पारी में 14 छक्के और 9 चौके शामिल रहे।वैभव का ये 10 दिनों के अंदर दूसरा शतकहै। वैभव ने 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार की ओर से 108 रन बनाए थे।

मेस्सी भारत दौरे में धूम मचाने के लिए तैयार, लेकिन 2011 की तरह नहीं दिखेगा फुटबॉल जादू

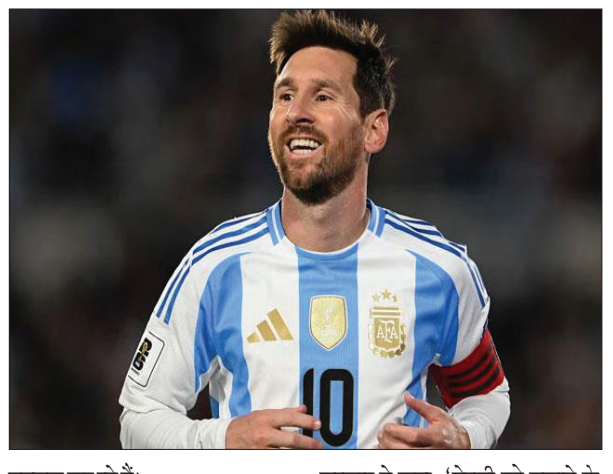

कोलकाता (एजेंसी)। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी की 2011 के बाद शनिवार से शुरू होने वाली पहली भारतीय यात्रा चकाचौंध से भरपूर होगी लेकिन इसमें फुटबॉल का खास जादू देखने को नहीं मिलेगा। मेस्सी का यह दौरा यह 2011 की तुलना में पूरी तरह से अलग होगा जब यहां साल्ट लेक स्टेडियम में दर्शकों ने सुपरस्टार के पांवों का जादू देखा था। तब फीफा मैत्री मैच में अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से हराया था और 85,000 से अधिक प्रशंसक स्टेडियम में जमा हुए थे। कुछ दर्शक तो स्टैंड के किनारों पर भी बैठे थे।

आठ बार बैलोन डीओर जीतने वाले मेस्सी इस बार 'जीओएटी इंडिया टूर 2025' में फुटबॉल खेलने वाले नहीं हैं। यह पूरी तरह से प्रचार और व्यावसायिक रूप से आयोजित कार्यक्रम है, जो शनिवार को यहां शुरू होगा और सोमवार को नई दिल्ली में समाप्त होगा। फिर भी एक ऐसे शहर के लिए यह बेहद खास है, जिसने कभी माराडोना तो कभी पेले को सिर आंखों पर बिठाया तो कभी अपने फुटबॉल प्रेम से डुंगा को चकाचौंध किया और रोनाल्डिन्हो को गले लगाया। इसे देखते हुए फुटबॉल नहीं खेलने के बावजूद यह शहर मेस्सी को अपने सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है।

सॉल्ट लेक स्टेडियम में कार्यक्रम, 7,000 की टिकट

आयोजकों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के लिए 78,000 सीटें सुरक्षित रखी हैं। यहां मेस्सी शनिवार को 45 मिनट तक चलने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके लिए टिकटों की कीमत 7,000 रुपए तक है। यह देखना हालांकि बाकी है कि फुटबॉल प्रेमी इस कार्यक्रम के प्रति कितना उत्साह दिखाते हैं। मेस्सी भारत में 72 घंटे से भी कम समय बिताएंगे, लेकिन इस दौरान वह चार महानगरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे।

कई दिग्गजों से मिलेंगे मेस्सी

अपनी इस संक्षिप्त दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज, बॉलीवुड हस्तियां और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ निर्धारित बैठक भी शामिल है। मेस्सी के प्रशंसकों में से एक भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का भी 14 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले टी20 मैच के बाद उनसे मिलने की उम्मीद है। मेस्सी का पिछला भारत दौरा फुटबॉल प्रेमियों की स्मृतियों में आज भी जीवंत बना हुआ है, जब उन्होंने तीन सितंबर, 2011 को अपने पांवों का जादू दिखाकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। भले ही वह उस मैच में गोल नहीं कर पाए थे लेकिन उन्हें अपने सामने खेलते हुए देखना भी बहुत बड़ा रोमांच था।

मेस्सी के दौरे का मुख्य आकर्षण

मेस्सी के वर्तमान दौरे का मुख्य आकर्षण रविवार को मुंबई में होने वाला 45 मिनट का फैशन शो होगा जिसमें यह दिग्गज फुटबॉलर लंबे समय तक अपने साथी रहे लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल के साथ भाग लेगा। मेस्सी के इस दौरे के प्रमोटर सतद्रु दत्ता ने कहा, 'इसमें मशहूर मॉडल, क्रिकेटर, बॉलीवुड हस्तियां, बिजनेसमैन शामिल होंगे। टाइगर और जैकी श्रॉफ, जॉन अब्राहम और अन्य लोग भी इसमें शिरकत करेंगे।% सुआरेज एक स्पेनिश संगीत कार्यक्रम में भी प्रस्तुति देंगे। आयोजकों ने मेस्सी से 2022 के विश्व कप विजेता अभियान से जुड़ी कुछ यादगार वस्तुएं लाने का अनुरोध किया है, जिनकी मुंबई में नीलामी की जाएगी।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम से पहले क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) में पैडल कप का आयोजन किया जाएगा। मेस्सी कोलकाता में ईएम बाईपास पर स्थित एक पांच सितारा होटल में ठहरेंगे और सुबह प्रायोजकों के साथ विशेष मुलाकात और अभिवादन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कोलकाता में अब VIP रोड पर श्रीभूमि क्लॉक टॉवर (बिग बेन की प्रतिकृति) के पास एक नया 'मेस्सी लैंडमार्क' भी होगा, जिसमें अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान की ट्रॉफी को ऊपर उठाए हुए 70 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा लगाई गई है।

सुरक्षा कारणों से इसका अनावरण मेस्सी के होटल स्थित कमरे से ही वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। मेस्सी के 25 गुणा 20 फीट के एक भित्ति चित्र का भी अनावरण किया जाएगा। बाद में इसे साल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी को भेंट किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद मेस्सी दोपहर दो बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। कोच्चि में होने वाला मेस्सी का प्रस्तावित मैत्री मैच रद्द होने के बाद हैदराबाद को उनके कार्यक्रम में जोड़ा गया था। हैदराबाद पहुंचने के बाद मेस्सी जीओएटी कप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल होंगे जिसमें सात सात खिलाड़ियों के बीच प्रदर्शनी मैच, पेनल्टी शूटआउट, युवा प्रतिभाओं के लिए एक मास्टरक्लास और संगीतमय प्रस्तुति भी शामिल है।

पीएम मोदी से मुलाकात और दौरे का समापन

मेस्सी अपने दौरे का समापन दिल्ली में करेंगे, जहां वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस साल की शुरुआत में गोथिया कप, डाना कप और नॉर्वे कप में शानदार जीत हासिल करने वाले मिनर्वा अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मेस्सी की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एक प्रदर्शनी मैच भी आयोजित किया जाएगा जिसमें 9-9 खिलाड़ी भाग लेंगे। मेस्सी के इस दौरे को लेकर हर कोई उत्साहित है और यही वजह है कि कुछ पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आमंत्रित न किए जाने पर 'दुखी और अपमानित' महसूस कर रहे हैं।

पेले के खिलाफ 1977 में प्रदर्शनी मैच खेलने वाले भारत और मोहन बागान के पूर्व मिडफील्डर गौतम सरकार ने अपनी बात कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, 'यह सब केवल दिखावा है। मेस्सी तो सिर्फ हाथ मिलाने आ रहे हैं। जब पेले यहां आए थे तो हमारे साथ खेले भी थे।' सरकार ने कहा, 'मेस्सी को बुलाने के बजाय हमारा ध्यान देश में फुटबॉल को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। हमें भारतीय फुटबॉल को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और अतीत के गौरव को वापस लाना चाहिए।% भारत के पूर्व डिफेंडर सुब्रत भट्टाचार्य ने भी कहा कि वह अपमानित महसूस कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

रूसी विदेश मंत्री ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सराहा

मास्को, एजेंसी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव ने बुधवार को भारत की स्वतंत्र और बहु-आयामी विदेश नीति की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक मंच पर अपनी नीति स्वयं तय करने वाला देश है और सभी प्रमुख देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रख अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। रूस की संसद का उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल को संबोधित करते हुए लावरोव ने कहा, वैश्विक दक्षिण के कई देश ऐसी नीति अपना रहे हैं और हमारे अच्छे मित्र भारत ने इसे बेहतरीन तरीके से लागू किया है। भारत सभी पक्षों के साथ संबंध रखता है और यह उसकी मजबूत, स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत है। लावरोव ने कहा, रूस अपनी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य घरेलू विकास को बढ़ावा देना मानता है और यह लक्ष्य भारत की रणनीतिक सोच से मेल खाता है। उन्होंने बताया, दोनों देशों के उद्देश्यों व आकलनों की समानता हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान फिर स्पष्ट हुई। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तैयार किया है।

ऑस्ट्रेलिया- हत्यारोपी भारतवंशी को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई

क्वींसलैंड , एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के एक समुद्र तट पर 24 वर्षीय महिला की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह घटना 2018 में हुई थी। केर्न्स स्थित सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नर्स राजविंदर सिंह (41) को टोया कॉर्डिंगली की हत्या का दोषी पाया। न्यायमूर्ति लिंकन क्रॉली ने कहा, सिंह का हत्या का मकसद अज्ञात था और इसे अवसरवादी हत्या करार दिया। सिंह ने यह हत्या उस वक्त की जब कॉर्डिंगली अपने कुत्ते को टहला रही थी। कॉर्डिंगली पोर्ट डगलस में एक स्वास्थ्य खाद्य और फार्मेसी स्टोर में काम करती थीं और एक पशु आश्रय में स्वयंसेवा भी करती थी। हत्या के बाद सिंह भारत भाग गया और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता को छोड़ गया। जज ने कहा, उसने अपनी पत्नी, माता-पिता और बच्चों को ठीक से बात किए बिना ही देश छोड़ दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी एकमात्र चिंता अपने परिवार के लिए परिणामों की परवाह किए बिना अपनी जान बचाना थी।

थाईलैंड व कंबोडिया सीमा पर लड़ाई थमने के संकेत नहीं, लाखों विस्थापित

बैंकॉक, एजेंसी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर फिर से शुरू हुई लड़ाई थमने के बुधवार को भी कोई संकेत नहीं दिखे, बल्कि कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हन सेन ने भीषण युद्ध का संकल्प लिया। इस तनाव से दोनों देशों में लाखों विस्थापित लोग अस्थाई आश्रयों में शरण लेने के कारण दयनीय परिस्थितियों में आ गए हैं। थाई सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल सुरासंत कोंगसिरी ने बुधवार को बताया कि थाईलैंड के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लगभग चार लाख लोगों को निकाला गया है और चार सीमावर्ती प्रांतों में लड़ाई जारी रहने के दौरान लगभग 700 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा, कंबोडिया ने भी 1.27 लाख से अधिक ग्रामीणों को निकाला है और सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए हैं। थाईलैंड की सेना ने कहा, इस सप्ताह हताहतों में पांच सैनिक शामिल हैं। कंबोडिया में 7 लोग मरे और 20 अन्य घायल हुए हैं। हालांकि उसने बुधवार को आंकड़े अपडेट नहीं किए। इस बीच कंबोडिया ने थाईलैंड में मंगलवार से शुरू हुए 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों से अपनी पूरी टीम को वापस बुला लिया है।

प्रतिनिधि सभा से रक्षा विधेयक पारित, सैनिकों का वेतन बढ़ाने और हथियार खरीद प्रक्रिया बदलने का प्रावधान

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक अहम रक्षा नीति विधेयक को पारित किया। इस विधेयक में 900 अरब डॉलर के सैन्य कार्यक्रमों को मंजूरी देने की बात कही गई है। इसमें सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाने और रक्षा मंत्रालय द्वारा हथियारों की खरीद के तरीके में सुधार करने का प्रावधान शामिल है। यह बिल ऐसे समय में आया है, जब रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस (संसद) और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच सैन्य प्रबंधन को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। इस विधेयक का नाम 'राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम' (एनडीएए) है। इस विधेयक को दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है और व्हाइट हाउस ने भी यह कहते हुए इसका मजबूती से समर्थन किया है कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुरूप है। फिर भी इस तीन हजार से अधिक पन्नों वाले विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जो रक्षा मंत्रालय पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से हैं। इनमें कैरिबिया में नावों पर हमलों पर अधिक जानकारी मांग, यूरोप में यूक्रेन जैसे सहयोगियों को समर्थन देने जैसे प्रावधान भी हैं।

नेपाल में संविधान संशोधन की तैयारी, चुनाव सुधारों के लिए सरकार और 'जेन-जी' में हुआ 10 सूत्रीय समझौता

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल की अंतरिम सरकार मौजूदा संविधान में संशोधन की दिशा में कदम उठाएगी। इन संशोधनों का मकसद आबादी के आधार पर पूरी तरह इसके अनुरूप और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना व प्रमुख सरकारी पदों पर चुने गए अधिकारियों के लिए कार्यकाल की सीमा तय करना है। 'जेन-जी' प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बुधवार रात को हुए 10 सूत्रीय समझौते के अनुसार एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सिफारिश आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ और 'जेन-जी' प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोग को प्रगतिशील संवैधानिक बदलावों के लिए सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा जाएगा, जो 'जेन-जी' प्रदर्शनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगी, जिन्होंने पिछली केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को गिराया था। इसके बाद नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनाई गई। आयोग किसी खास समुदाय की आबादी के आधार पर पूरी तरह से अनुरूप और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रणाली में जरूरी सुधारों की सिफारिश करेगा। फिलहाल, नेपाल का संविधान प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक मिश्रित चुनावी प्रणाली (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) का

प्रावधान करता है। 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली के तहत, 60 प्रतिशत प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जबकि बाकी 40 प्रतिशत को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना जाता है। समझौते के अनुसार आयोग राज्य के प्रमुख, तीनों स्तरों (संघीय, प्रांतीय और स्थानीय) के प्रमुखों और कार्यकारी निकायों के सदस्यों के लिए अधिकतम दो कार्यकाल (कुल 10 वर्ष से अधिक नहीं) की कार्यकाल सीमा की सिफारिश भी करेगा। फिलहाल कार्यकाल की सीमा सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय सरकारों के प्रमुखों पर लागू होती है। संघीय या प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों के लिए कोई कार्यकाल सीमा नहीं है। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि राजनीतिक नेता बार-बार सत्ता में आते रहे और कोई नतीजा नहीं दिया, जिसे 'म्यूजिकल चेयर्स' जैसा खेल बताया गया। इसी से नेपाली युवाओं में भारी असंतोष पैदा हुआ। यह गुस्सा इस साल सितंबर में हुए 'जेन-जी' प्रदर्शनों में स्पष्ट रूप से दिखा। 'जेन-जी' आंदोलन से पहले नेपाल में वर्षों तक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के केपी शर्मा ओली और नई गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' समेत शीर्ष नेताओं ने बार-बार सरकार की बागडोर संभाली। सितंबर में 'जेन-जी' प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राजनीतिक दलों के कई नेता आए। प्रतिनिधि सभा आयोग, प्रांतीय सभा और स्थानीय स्तर के चुने हुए पदों के लिए उम्मीदवारी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के प्रस्ताव का भी अध्ययन करेगी। अभी संघीय संसद और प्रांतीय सभाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, जबकि स्थानीय स्तर के चुने हुए पदों के लिए उम्र 21 साल है। राज्य निकायों में राजनीतिक वफादारी और आर्थिक हितों के आधार पर नियुक्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए आयोग ऐसी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार मौजूदा संरचनाओं में जरूरी सुधारों की जांच करेगा। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली सरकार बनने पर उसके दो गठबंधन साझेदारों- नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) ने राजनीतिक स्थिरता के लिए संविधान संशोधन का वादा किया था। दोनों पार्टियों के नेताओं ने यह राय व्यक्त की थी कि आनुपातिक चुनावी प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए, ताकि एक ही पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल कर सके। हालांकि सितंबर में 'जेन-जी' विरोध प्रदर्शनों के बाद उस सरकार के गिरने से पहले संविधान में संशोधन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

क्या फिर गृहयुद्ध की दल-दल में फंसा यमन? यूएई समर्थित एसटीसी ने तेल-समृद्ध इलाकों पर किया कब्जा

सना, एजेंसी। यमन में कई साल से चल रही अशांति बीच दक्षिणी हिस्से में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) ने देश के तेल-समृद्ध इलाकों हदरामौत और महरा के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे अब तक बनी हुई हाल की शांति टूट गई है और क्षेत्र में नए तनाव बढ़ने लगे हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से यमन में लड़ाई कुछ कम हो गई थी, क्योंकि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच एक तरह का समझौता हो गया था। लेकिन एसटीसी की इस नई कार्रवाई से हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं।

एसटीसी दक्षिण यमन को अलग देश बनाने की मांग करने वाला बड़ा संगठन है। इसे यूएई का राजनीतिक और सैन्य समर्थन मिलता है। यह संगठन 2017 में बना था और दक्षिणी यमन के बड़े हिस्से में इसकी पकड़ मजबूत है। एसटीसी के प्रमुख ऐदारूस अल-जुबैदी देश की राष्ट्रपति परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं।

अब समझिए कैसे शुरू हुआ यमन का संकट : बता दें कि 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को देश छोड़ना पड़ा। एक साल बाद 2015 में सऊदी अरब और यूएई इस युद्ध में सरकार की

मदद के लिए शामिल हुए। हालांकि तब से यमन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उत्तरी इलाके में हूतियों के कब्जें में और दूसरी ओर दक्षिणी हिस्से सरकार व उसके समर्थक समूहों के नियंत्रण में था।

तेल क्षेत्रों पर कब्जे से मामला कैसे बढ़ा : दरसअल इसी महीने एसचीसी ने अचानक हदरामौत में मार्च करते हुए बड़े तेल प्रतिष्ठानों पर कब्ज़ा कर लिया, जिनमें यमन की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोमसीला भी शामिल है। इससे पहले सऊदी समर्थित स्थानीय कबीलों ने तेल राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करते हुए इस इलाके पर कुछ समय के लिए कब्जा किया था।

ऐसे में एसटीसी ने इसी को मौका बनाकर अपनी ताकत बढ़ाई और इलाके पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। इसके बाद एसटीसी ने पड़ोसी प्रांत महरा में भी प्रवेश किया और ओमान सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया। अदन में उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर भी नियंत्रण कर लिया, जहां सरकारी नेतृत्व बैठता है।

मोरक्को के एक शहर में दो इमारतें गिरीं, 22 की मौत; दरारों की अनदेखी बन गई मौत की वजह

रबात, एजेंसी। मोरक्को के ऐतिहासिक शहर फेज में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। पुराने इलाके में दो चार-मंजिला इमारतें अचानक ढह गईं, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। यह घटना उस क्षेत्र में हुई, जहां इमारतों के खराब हालात की शिकायतें पहले से थीं। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई परिवार मलबे में दब गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, अल-मुस्तक़बल इलाके में स्थित दोनों इमारतों में आठ परिवार रहते थे। रात के समय ये इमारतें अचानक भरभराकर गिर पड़ीं। सरकारी एजेंसी के अनुसार, दोनों इमारतों में लंबे समय से दरारें थीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जैसे ही प्रशासन को घटना की जानकारी मिली, पुलिस, स्थानीय अधिकारी और सिविल प्रोटेक्शन टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। सरकारी मीडिया वेबसाइट एसएनआरटी ने बताया कि दोनों इमारतों में काफी समय से दरारें दिख रही थीं। लोगों ने इस बारे में चिंता भी जताई थी, लेकिन कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अचानक गिरने का कारण क्या था, लेकिन माना जा रहा है कि संरचनात्मक कमजोरी ही मुख्य वजह बनी। हालांकि अमर उजाला इसकी पुष्टि नहीं करता है। फेज मोरक्को का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पुराना राजधानी शहर है, जिसकी स्थापना आठवीं सदी में हुई थी। कुछ समय पहले यह शहर सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण सुर्खियों में रहा था। लोगों ने खराब जीवन स्तर, महंगाई और कमजोर सार्वजनिक सेवाओं के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए थे। यह गुस्सा इतना बढ़ गया था कि कुछ जगहों पर आंदोलन हिंसा में बदल गया। मोरक्को के बड़े शहर और आर्थिक केंद्र देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से में हैं, जबकि बाकी इलाकों की अर्थव्यवस्था अब भी खेती, मछली पालन और पर्यटन पर निर्भर है। सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वर्ल्ड कप 2030 से पहले स्टेडियम निर्माण पर जोर दे रही है। लेकिन इसी बीच ग्रामीण और छोटे शहरों में गरीबी और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ी है।

डेमोक्रेट्स ने उठाए ट्रंप की नीतियों पर सवाल, चेताया- ज्यादा टैरिफ से भारत को खो देगा अमेरिका

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़े फैसलों को लेकर डेमोक्रेट्स ने उन्हें चेताया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ सिस्टम और नई दिल्ली के प्रति टकराव वाला रवैया सही नहीं है। यह अमेरिका के सबसे अहम साझेदारों में से एक को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी ऑन साउथ एंड सेंट्रल एशिया की यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान डेमोक्रेटिक रैंकिंग मेंबर सिडनी कामलेगर-डोव ने ट्रंप पर दशकों की द्विदलीय प्रगति को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप को एक अच्छा द्विपक्षीय संबंध सौंपा था। इसमें एक फिर से सक्रिय क्वाड, एक उभरती हुई रक्षा तकनीक

साझेदारी और एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर का हवाला दिया गया था, लेकिन ट्रंप ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इतिहास ट्रंप को कड़ा सबक सिखा सकता है, जब तक वह अपना रास्ता नहीं बदलते। ऐसी सूरत में ट्रंप वह अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, जिन्होंने भारत को खो दिया। डेमोक्रेट्स ने कहा, 'आप (ट्रंप) रणनीतिक साझेदारों को अपने दुश्मनों की गोद में धकेलकर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते। मामला ट्रंप के 25 प्रतिशत 'लिबरेशन डे टैरिफ' का था। भारत के रूसी तेल के आयात से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था और भारत पर टैरिफ का कुल 50 प्रतिशत बोझ आ गया। उन्होंने ट्रंप की नीति को आत्मघाती बताते हुए कहा कि भारत पर लगाया गया टैरिफ वर्तमान में चीन पर लगाए गए टैरिफ से अधिक है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर की फीस लगाकर लोगों के बीच संबंधों पर हमला करने का भी आरोप लगाया, जिसमें से 70 प्रतिशत भारतीयों के पास हैं। उन्होंने इसे यूएस में भारतीयों के अविश्वसनीय योगदान का अपमान बताया। भारत के प्रमुख थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अमेरिकी सहयोगी ओआरएफ अमेरिका के ध्रुव जयशंकर ने कहा कि व्यापार वार्ता 13 फरवरी से पहले शुरू हुई थी और जुलाई तक, दोनों पक्ष एक समझौते के काफी करीब पहुंच गए थे। भारत सक्रिय रूप से मुक्त व्यापार सौदों पर काम कर रहा है और अगर वाशिंगटन में राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो एक समाधान हाथ में है। यह भी चेतावनी दी गई कि टैरिफ की वजह से चीन का मुकाबला करने और सप्लाई चेन को स्थिर करने सहित जरूरी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर खतरा मंडरा सकता है।

अंटार्कटिका के नीचे रोबोटिक मिशन ने गर्म धाराओं का रहस्य किया उजागर, वैश्विक जलवायु चिंताओं को बढ़ाया

अंटार्कटिका, एजेंसी। अंटार्कटिका की डॉटसन आइस शेल्फ के नीचे पहली बार किए गए रोबोटिक सर्वे ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि गर्म और खारा गहरा समुद्री जल बर्फ के बिल्कुल निचले हिस्सों तक बिना किसी बड़े मिश्रण के क्षैतिज रूप से बहते हुए सीधे ग्राउंडिंग लाइन तक पहुंच रहा है। वह संवेदनशील इलाका है जहां ग्लेशियर समुद्र तल को छोड़कर तैरना शुरू करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन ने पिघलन की वास्तविक प्रक्रिया को समझने की दिशा में बड़ा मोड़ दिया है और समुद्र-स्तर में भविष्य की वृद्धि के अनुमानों को लेकर वैज्ञानिक समुदाय को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। यूईए के वैज्ञानिकों ने 2022 में बोटी मैकबोटफेस नामक पानी के भीतर चलने वाले उन्नत स्वायत्त रोबोट की मदद से अमुंडसेन सागर में स्थित डॉटसन आइस शेल्फ के नीचे लगभग 100 किलोमीटर लंबा पहला गहन सर्वेक्षण संचालित किया। मिशन ने समुद्री तल से करीब 100 मीटर ऊपर रहकर तापमान, लवणता, ऑक्सीजन स्तर, धारा की रफ्तार और जल मिश्रण के आंकड़े जुटाए जो अब तक अंटार्कटिका की कठिन परिस्थितियों में लगभग असंभव माने जाते थे।डॉटसन विश्व के उन क्षेत्रों में गिना जाता है जहां ग्लेशियर सबसे तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र की गहराइयों से आने वाली गर्मी को इसका प्रमुख कारण बताया जाता है। लेकिन अब इस शोध ने दिखाया कि गर्मी किस तरह बर्फ के आधार तक पहुंचती है, यह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है।

गर्म पानी ऊपर नहीं उठता, सीधे ग्राउंडिंग लाइन की ओर बहता है : सबसे बड़ा खुलासा यह है कि गर्म, गहरा और अधिक खारा पानी पारंपरिक धारणा के विपरीत ऊपर की ओर मिलकर पिघलन नहीं बढ़ाता, बल्कि क्षैतिज दिशा में तेजी से बहते हुए सीधे ग्राउंडिंग लाइन तक पहुंचता है। इसका मतलब है ग्लेशियर नीचे से अधिक पिघलते हैं। उनकी संरचना तेजी से कमजोर होती है तथा पीछे हटने की रफ्तार बढ़ती है और समुद्र में बर्फ का नुकसान कई गुना बढ़ता है। यह प्रक्रिया वैश्विक समुद्र-स्तर बढ़ोतरी में बड़ा योगदान देती है, क्योंकि अमुंडसेन सागर बेसिन में होने वाला बर्फ-नुकसान अकेले पृथ्वी के भविष्य का समुद्र-स्तर तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। रोबोट ने 5-10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की समुद्री धारा दर्ज की। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि तेज धारा ही पानी के मिश्रण को नियंत्रित करती है, लेकिन निष्कर्ष इसके बिल्कुल विपरीत निकले। समुद्र तल की ढलान कभी-कभी 45 डिग्री तक ही गर्म पानी को ऊपर धकेलने या नीचे रोके रहने का वास्तविक कारक है। जहां ढलान तीव्र है, वहां गर्म पानी कुछ ऊंचाई तक मिश्रित होता है।

चुनाव को लेकर ट्रंप ने फिर से जेलेंस्की को लताड़ा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी दिया जवाब

कीव, एजेंसी। रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति समझौते पर जेलेंस्की की असहमति के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से कीव में चुनाव का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेलेंस्की पद पर बने रहने के लिए युद्ध का बहाना बना रहे हैं... जेलेंस्की को युद्ध को लेकर यथार्थवादी होना होगा और सोचना होगा कि वह अगला चुनाव कब करवा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप के इसी तरह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि यदि सहयोगी देश युद्धकाल में सुरक्षित मतदान की गारंटी दें और यदि यूक्रेन के चुनावी कानून में संशोधन किया जा सके तो यूक्रेन तीन महीने के भीतर चुनाव करा सकता है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते जेलेंस्की के ऊपर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'वहाँ लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। आप जानते हैं, वे लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह लोकतंत्र नहीं रह जाता।' इस पर जेलेंस्की ने कहा ने कहा कि वह चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन मतदान के लिए उन्हें यूरोप और अमेरिका की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन सुरक्षित होता है तो वह 60 से 90 दिनों के भीतर मतदान कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'चुनाव कराने के लिए दो मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है जिनमें पहला है सुरक्षा- चुनाव कैसे कराए जाएं, हमलों और मिसाइल हमलों के बीच चुनाव कैसे कराए जाएं और दूसरा, हमारी सेना से संबंधित प्रश्न- वे कैसे मतदान करेंगे। और दूसरा मुद्दा चुनावों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधायी ढांचा है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से ऐसे विधायी प्रस्ताव तैयार करने को कहा है जो यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान चुनाव कराने की अनुमति देने वाला हो। आपको बता दें, जेलेंस्की का कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। हालांकि, युद्ध के चलते उनके कार्यकाल को लगातार बढ़ाया जाता रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जेलेंस्की के कार्यकाल संबंधी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं।

11 माह बाद सामने आईं मारिया मचाडो, क्यों देश छोड़ने पर हुईं मजबूर

ओस्लो, एजेंसी। वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो करीब 11 महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दीं। वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक होटल की बालकनी पर नजर आईं, जहां उनकी बेटी ने उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया। मचाडो होटल की बालकनी पर समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन करती दिखीं। इस दौरान बाहर लोग 'फ्रीडम, फ्रीडम' और 'धन्यवाद' के नारे लगा रहे थे। बाद में वह होटल से बाहर आकर समर्थकों से मिलीं, जहां उनके साथ परिवार और उनके करीबी सहयोगी भी थे।

क्यों छिपी हुई थी मचाडो : बता दें कि जनवरी 2024 में कराकास में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा को खतरा होने के कारण वे छिपकर रह रही थीं। उनकी उम्मीद थी कि वे खुद पुरस्कार लेने पहुंच पाएंगी, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच सकीं। उन्होंने एक फोन कॉल में कहा कि कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी यात्रा को संभव बनाने की कोशिश की। उनकी बेटी एना कोरीना सोसा ने पुरस्कार लेते हुए कहा कि मेरी मां एक आजाद वेनेजुएला में जीना चाहती हैं और कभी हार नहीं मानेंगी।

माचाडो ने बनाई थी ये योजना : माचाडो ने पिछले साल मादुरो को चुनौती देने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया। इसके कारण उन्होंने सेवानिवृत्त कूटनीतिज्ञ एडमंडो गोंजालेज का समर्थन किया। चुनाव से पहले और बाद में कई लोगों ने माचाडो का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देश छोड़कर निर्वासन नहीं लिया।

वेनेजुएला के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं : वहीं माचाडो के विदेश जाने को लेकर वेनेजुएला में लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। कैराकस की एक

कर्मचारी जोसफिना पाज ने कहा कि अगर उन्होंने देश छोड़ा है, तो ठीक है। इस महिला ने लोकतंत्र के लिए कई बलिदान दिए हैं। अब उन्हें अपने परिवार और बच्चों के पास जाना चाहिए और विदेश से संघर्ष जारी रखना चाहिए। वहीं, दुकानदार जोसे हर्टाडो ने उन्हें देशद्रोही कहा, क्योंकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति का समर्थन करती हैं।

नोबेल समिति ने क्या कहा : वहीं नोबेल समिति के प्रमुख ने कहा कि मचाडो ने बहुत खतरनाक हालात के बावजूद ओस्लो आने की पूरी कोशिश की और वे सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि वेनेजुएला लंबे समय से राजनीतिक संकट और दमन का सामना कर रहा है। मचाडो ने पिछले साल विपक्षी प्राइमरी जीती थी और राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन मादुरो सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया। उनकी जगह विपक्ष ने एडमुडो गोंजालेज को उतारा, जिन्हें बाद में गिरफ्तारी वारंट के कारण स्पेन में शरण लेनी पड़ी। चुनाव से पहले और बाद में दमन, गिरफ्तारियों और मानवाधिकार उल्लंघनों की कई शिकायतें हुई।

पुरस्कार समारोह में लैटिन अमेरिकी नेताओं की मौजूदगी : कार्यक्रम में अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पनामा और पराग्वे के राष्ट्रपति भी मचाडो के समर्थन में पहुंचे। नोबेल समिति ने मचाडो को 'असाधारण साहस की मिसाल' बताया और कहा कि वेनेजुएला 'क्रूर निरंकुश शासन' में बदल चुका है।

मचाडो की बेटी ने बढ़कर सुनाया उनका संदेश : उनके भाषण को उनकी बेटी ने पढ़कर सुनाया। इसमें कहा गया कि यह सम्मान पूरे वेनेजुएला के लोगों का है, और वे जल्द ही अपने परिवार और देशवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। संदेश में यह कहा कि लोकतंत्र पाने के लिए हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ने की हिम्मत रखनी होगी।

मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक लव जैन द्वारा स्वास्तिका क्रिएशन, स्कीम-3, ओखला फेस-II, नई दिल्ली-110020 से छपवाकर 400/12, जैकबपुरा, न्यू रेलवे रोड, अपोजिट वर्मा (ईएनटी) से प्रकाशित किया, संपादक लव जैन पीआरबी एक्ट के अंतर्गत रचनाओं के चयन के लिए उत्तरदायी। सभी विवादों का निपटारा गुड़गांव न्यायालय में होगा।